सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" पछतावा अतीत नहीं बदल सकता ,
और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती।
इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है।।...!! "
अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–122 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शुक्रवार 22 मई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

अगले 24 घंटे छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में लू का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

दोपहर में घर से न निकलने की सलाह

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। बलौदाबाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जांजगीर–चांपा, कबीरधाम, खैरगढ़ छुईखदान गंडई, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सक्ती और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलों में अलग–अलग स्थानों पर लू चलने की संभावना है।

तापमान में बढ़ोतरी के कारण दिन में तेज गर्म हवाएं चलेंगी। विभाग ने लोगों से दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की अपील की है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए ज्यादा पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप में निकलते समय सिर ढकने की सलाह दी है। लू के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

स्थान	तापमान
धमतरी	45.8
बेमेतरा	45.4
बालोद	44.7
कबीरधाम	44.7
बिलासपुर	44.6

प्रचंड गर्मी से तप रहा देश : कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार

देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और हालिया हीट इंडेक्स आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारत और मध्य भारत के कई शहरों में रिकॉर्डतोड़ गर्मी दर्ज की गई है।

कई राज्यों में गर्म रातों की चेतावनी

मौसम विभाग ने कई राज्यों में गर्म रातों को लेकर भी चेतावनी जारी की है। ओडिशा में 22 से 25 मई तक, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में 22 और 23 मई को, बिहार में 22 मई को व हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 22 मई को रात के समय तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

मानसून को लेकर क्या जानकारी दी गई?

इधर, मौसम विभाग ने दक्षिण–पश्चिम मानसून को लेकर भी जानकारी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन से चार दिनों के दौरान दक्षिण–पश्चिम मानसून के दक्षिण–पूर्व अरब सागर, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण–पश्चिम और दक्षिण–पूर्व बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के शेष हिस्सों और पूर्व–मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।

इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम बदला, अब होगा राजकुमारी इन्दिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय

राज्य शासन ने दी मंजूरी, राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर हुआ निर्णय

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का नाम अब राजकुमारी इन्दिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय होगा। राज्य शासन ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने 21 मई को राज्यपाल के नाम से पत्र जारी कर स्वीकृति दी।

राज्यपाल ने दिया था सुझाव

विश्वविद्यालय का नाम बदलने का सुझाव राज्यपाल एवं कुलाधिपति रमेन डेका ने दिया था। उन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्वविद्यालय की मूल पहचान और संस्थापक राजपरिवार के योगदान को सम्मानजनक रूप से संरक्षित करने की बात कही थी। इसके बाद कुलपति प्रो. डॉ. लवली शर्मा की विशेष पहल पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर प्रस्ताव शासन को भेजा था।

कुलपति के प्रयास से मिले दस्तावेज

शासन ने नाम परिवर्तन के लिए जरूरी दस्तावेज मांगे थे जो विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं थे। कुलपति के अथक प्रयास के बाद दस्तावेज शासन को उपलब्ध कराए गए। इसके बाद प्रशासनिक परीक्षण कर प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।

राजपरिवार के योगदान को किया सम्मान

नाम परिवर्तन का उद्देश्य खैरागढ़ राजपरिवार की दानशीलता, कला संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को अक्षुण्ण बनाए रखना है। यह विश्वविद्यालय देश–प्रदेश में कला एवं संगीत शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में शामिल है। यहां से बड़ी संख्या में कलाकार और संगीतज्ञ निकले हैं।

कुलपति प्रो. डॉ. लवली शर्मा ने कहा कि यह निर्णय संस्थान की गौरवशाली परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और संस्थापक परिवार के योगदान को स्थायी सम्मान देगा।

रावघाट रेल परियोजना से बदली बस्तर की तस्वीर अक्टूबर माह से सीधे चलेगी लौह अयस्क की रैक

95 किमी लंबी परियोजना पर भिलाई इस्पात संयंत्र ने खर्च किए 1900 करोड़

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग–बस्तर

दशकों तक दुर्गम पहाड़ियों और नक्सल चुनौतियों से जूझता रहा बस्तर अब दल्लीराजहरा–रावघाट रेल परियोजना से विकास की नई पटरी पर दौड़ने को तैयार है। सेल–भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे की साझेदारी में बनी 95 किमी लंबी इस रेल लाइन की पूर्ण कमीशनिंग जून 2026 में प्रस्तावित है। 20 मई को रावघाट रेलखंड पर इंजन की सफल रोलिंग के साथ ही अक्टूबर 2026 से रावघाट माइंस से सीधे लौह अयस्क की रेक डिस्पैच का रास्ता साफ हो गया है।

1900 करोड़ से ज्यादा का निवेश, सुरक्षा पर 180 करोड़ खर्च

परियोजना की अनुमानित लागत 1854 करोड़ रुपये है, जिसमें से भिलाई इस्पात संयंत्र अब तक

1720 करोड़ का भुगतान कर चुका है। विद्युतीकरण पर अतिरिक्त 180 करोड़ खर्च किए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा के लिए एसएसबी और बीएसएफ की दो–दो बटालियन तैनात हैं। सेल ने 4 अर्ध–स्थायी और 21 स्थायी सुरक्षा शिविरों पर 180 करोड़ से अधिक खर्च किए।

यात्री सेवा से खुले रोजगार और शिक्षा के द्वार

2022 में दल्लीराजहरा–तरोकी यात्री ट्रेन शुरू होने के बाद बस्तर के लोगों को दुर्ग, भिलाई समेत बड़े शहरों तक सीधी पहुंच मिली है। इससे आदिवासी युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर बने हैं।

रोज 15 हजार टन लौह अयस्क ढुलाई का लक्ष्य

वर्तमान में अंतागढ़ साइडिंग से रोज 6000 टन लौह अयस्क भेजा जा रहा है। अक्टूबर से रावघाट से सीधे संचालन शुरू होने पर रोज चार रेक यानी करीब 15 हजार टन ढुलाई होगी। वर्ष 2026–27 में अंतागढ़ और रावघाट से 4 से 5 मिलियन टन लौह अयस्क मिलने का अनुमान है। परियोजना पूरी होने पर सालाना 6 से 7 मिलियन टन आपूर्ति संभव होगी।

बीएसपी के विस्तार का आधार

भिलाई इस्पात संयंत्र की मौजूदा लौह अयस्क जरूरत रोज 32 हजार टन है। हॉट मेटल उत्पादन 6.5 एमटीपीए से बढ़ाकर 2031 तक 10.5 एमटीपीए करने का लक्ष्य है। रावघाट परियोजना संयंत्र की दीर्घकालिक कच्चा माल सुरक्षा का आधार बनेगी। रावघाट स्टेशन पर तीन यात्री प्लेटफॉर्म और एक अलग गुड्स प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। संयंत्र के अनुसार यह परियोजना केवल औद्योगिक जरूरत नहीं, बल्कि बस्तर के भीतरी क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने का दीर्घकालिक आधार है।

आर्य नगर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस

पति–पत्नी फंदे पर लटके मिले, दो बच्चे बिस्तर पर मृत, सुसाइड नोट में पारिवारिक विवाद का जिक्र

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

मोहन नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर में मंगलवार को एक परिवार के चार सदस्यों की मौत से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

मृतकों की पहचान गोविंद साहू 45 वर्ष, उनकी पत्नी चंचल साहू 40 वर्ष, पुत्री दृष्णा साहू 13 वर्ष और पुत्र यशांत साहू 11 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार पति–पत्नी फंदे पर लटके मिले, जबकि दोनों बच्चे बिस्तर पर मृत अवस्था में थे। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल यूनिट की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए।

पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पारिवारिक विवाद की बात लिखी है। थाना मोहन नगर में मर्ग कायम कर मामले की सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

सलोनी में खत्म हुआ सामाजिक बहिष्कार, प्रशासन की पहल पर ग्रामीणों में बनी सहमति

राजनांदगांव। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम सलोनी में चल रहे सामाजिक बहिष्कार का जिला प्रशासन की पहल पर निराकरण हो गया है। गांव के 6 ग्रामीणों को सामाजिक बहिष्कार कर अलग कर दिया गया था। अब दोनों पक्षों की सहमति से बहिष्कार खत्म कर दिया गया है। ग्राम सलोनी निवासी लेखराम वर्मा और पांच अन्य ग्रामीणों ने सामाजिक बहिष्कार खत्म कराने के लिए आवेदन दिया था। आवेदकों ने बताया कि बहिष्कार के कारण उन्हें कृषि कार्य, त्योहार और वैवाहिक कार्यक्रमों में परेशानी हो रही थी। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देश पर तहसीलदार अमिय श्रीवास्तव, टीआई सुमन जायसवाल और अतिरिक्त तहसीलदार सोनित मेरिया ने ग्राम सलोनी में सामाजिक और ग्राम समिति की बैठक ली। बैठक में दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। इसके बाद उभयपक्षों ने सामाजिक बहिष्कार खत्म कर मिल–जुलकर रहने पर सहमति दी। ग्रामीणों ने भविष्य में किसी का भी सामाजिक बहिष्कार नहीं करने का भरोसा दिया।

सीतापुर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, दोस्त ने ही ईंट और कड़े से की थी हत्या

टावर मैदान में शुरू हुआ विवाद सामुदायिक शौचालय के पास बना खूनी वारदात, आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़

कोतरारोड़ थाना क्षेत्र के सीतापुर में 15 मई को मिले युवक के शव के ब्लाइंड मर्डर का रायगढ़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक तिलक वर्मा की हत्या उसके ही दोस्त अमन कुमार बसोड ने मामूली विवाद में बेरहमी से की थी। पुलिस ने फरार आरोपी को दबोचकर रिमांड पर भेज दिया है।

ऐसे सुलझी अंधे कत्ल की गुत्थी

15 मई की सुबह सीतापुर स्थित सामुदायिक शौचालय के पास तिलक वर्मा (21) का शव मिला था। सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर डीएसपी सुशांतो बनर्जी और थाना प्रभारी शील कुमार आदित्य की टीम ने जांच शुरू की। घटनास्थल से खून से सनी ईंट और पत्थर मिले। पूछताछ में पता चला कि घटना की रात तिलक और उसके दोस्त अमन बसोड (21) निवासी भगवानपुर के बीच टावर मैदान में विवाद हुआ था। घटना के बाद से अमन फरार था।

शराब न मिलने पर फिर हुआ विवाद

गिरफ्तारी के बाद आरोपी अमन ने बताया कि 14 मई की रात टावर मैदान में सीमेंट पोल तोड़ने की बात पर विवाद हुआ। मारपीट में उसकी शर्ट फट गई तो तिलक ने अपना टी–शर्ट पहनने को दिया। बाद में बोरिंग के पास फिर झगड़ा हुआ और दोनों घायल हुए। तिलक उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भी ले गया। रात में दोनों बाइक से सीतापुर पहुंचे। शराब न मिलने पर सामुदायिक भवन के पास बैठ गए। वहां पुराने विवाद पर फिर झगड़ा हुआ। गुस्से में

अमन ने हाथ में पहने लोहे के कड़े और ईंट से तिलक के सिर, गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह दोस्तों को बताकर फरार हो गया।

कड़े और कपड़े जब्त

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पुराना बस स्टैंड के पास से पकड़ा। उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कड़ा और घटना के वक्त पहने कपड़े जब्त किए गए। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया। मामले में थाना प्रभारी शील कुमार आदित्य, एएसआई मनमोहन बैरागी, प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू, आरक्षक चुडामणी गुप्ता और राजेश खांडे की अहम भूमिका रही।

एसएसपी का सख्त संदेश

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा, हत्या जैसे गंभीर अपराध कर फरार होने वाले अपराधियों को रायगढ़ पुलिस ऑपरेशन तलाश में गिरफ्तार कर रही है। कानून से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपराधियों पर कड़ी और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना : दुर्ग रीजन में 9,715 घरों पर लगे सोलर पैनल

6 हजार से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल हुआ शून्य

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग विद्युत रीजन (दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले) के उपभोक्ता अब अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत दुर्ग रीजन में 06 हजार से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल अब शून्य आ रहा है, जबकि हजारों उपभोक्ता हर महीने आने वाली भारी-भरकम बिल से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। रीजन में अब तक 24,657 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 19,422 उपभोक्ताओं ने वेंडर का चयन कर लिया है। क्षेत्र में कुल 9,715 उपभोक्ताओं के घरों में लगभग 35.819 मेगावॉट क्षमता के सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं।

सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक संजय खंडेलवाल ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि सरकार आपको उपभोक्ता से ऊर्जादाता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 01 किलोवॉट का प्लांट प्रतिमाह 130 से 140 यूनिट बिजली उत्पादित करता है, जिस पर ?45,000 तक की कुल सब्सिडी मिलती है। योजना के अंतर्गत 02 किलोवॉट के प्लांट से प्रतिमाह अधिकतम 260 से 280 यूनिट उत्पादन होता है, जिस पर 90,000 तक की कुल सब्सिडी मिलती है। वहीं, 03 किलोवॉट क्षमता के प्लांट से प्रतिमाह लगभग 390 से 420 यूनिट बिजली बनती है, जिसमें 1,08,000 की सब्सिडी मिलती है। लागत की लगभग 60 प्रतिशत राशि सरकार स्वयं वहन कर रही है, शेष 40 प्रतिशत राशि के लिए बेहद कम ब्याज दर पर आसान बैंक लोन भी उपलब्ध है।

अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना कोई खर्च नहीं, बल्कि भविष्य का सबसे समझदारी भरा निवेश है। सोलर लगाने के बाद उपभोक्ता का बिजली बिल या ता नाममात्र का रह जाएगा, या फिर अतिरिक्त उत्पादन होने पर बिल्कुल शून्य हो जाएगा। सोलर पैनल लगवाने के लिए चाहे उपभोक्ता सब्सिडी के बाद की षेश राषि लोन लें या स्वयं राशि लगाएं, हर महीने बिजली बिल में होने वाली भरी बचत से ही मात्र 03-04 वर्षों में पूरी लागत वसूल हो जाएगी। इसके बाद उपभोक्ता जीवनभर मुफ्त बिजली का आनंद ले सकेंगे।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है, जहां उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद बिजली कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचकर सत्यापन करेंगे और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। पोर्टल पर कई अधिकृत वेंडर पंजीकृत हैं, जिनमें से उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। कार्यपालक निदेशक ने उपभोक्ताओं को फर्जी वेंडरों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही, कड़ी चेतावनी दी गई है कि जो वेंडर अनुबंध के तीन महीने बाद भी सोलर पैनल नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा मई महीने को मंथ ऑफ सोलर (सौर माह) के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत देश में सबसे अधिक आवेदन प्राप्त करने या सोलर पैनल लगाने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। अतः उपभोक्ताओं से अपील है कि छत्तीसगढ़ को देश में अव्वल और पुरस्कृत राज्य बनाने में अपना योगदान दें। यह निवेश ना केवल आज आपके पैसों की बचत करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। योजना का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं को विभाग ने सलाह दी है कि यदि कभी भरपूर धूप के बावजूद बिजली उत्पादन कम लगे, तो बस समय-समय पर सावधानीपूर्वक पानी से धोकर सोलर पैनलों की सफाई कर लें, ताकि आपका सोलर पैनल हमेशा पूरी क्षमता से कार्य करता रहे।

कार्यपालक निदेशक संजय खण्डेलवाल ने रेखांकित किया कि सरकार की मंशा है कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत पाने के लिए किसी शासकीय योजना पर आश्रित न रहना पड़े, बल्कि वे स्वयं अपनी छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर ऊर्जादाता बनें। जब आपके घर की छत पर आपका अपना सोलर प्लांट होगा और नेट मीटरिंग के जरिए बची हुई बिजली का पैसा सीधे मार्च के अंत में आपके खाते में आएगा या बिल में एडजस्ट होगा, तब सही मायनों में उपभोक्ता विद्युत के लिए आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह अभियान सिर्फ बिजली बिल को कम करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ देष को हरित और स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने की एक महत्वपूर्ण जन-भागीदारी है।

खास खबर

प्रगति नगर कैंप-1 में चल रही श्रीराम कथा में उमड़े श्रद्धालु, सर्व कल्याण समाज के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू हुए शामिल

अयोध्या धाम के नरेन्द्र राम दास कर रहे कथा वाचन, आयोजन समिति का जताया आभार

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

प्रगति नगर कैंप-1 स्थित श्री शिव हनुमंत धाम मंदिर एवं श्रीराम जानकी मंदिर कैंप-1 के संयुक्त तत्वावधान में श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा वाचक श्री श्री 1008 श्री राम हर्षण देवाचार्य के कृपापात्र अयोध्या धाम के नरेन्द्र राम दास जी महाराज के श्रीमुख से हो रही कथा का श्रद्धालु रसपान कर रहे हैं। बुधवार को सर्व कल्याण समाज के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू कथा में शामिल हुए। उन्होंने व्यासपीठ का आशीर्वाद लिया और कथा श्रवण की।

आयोजन को सफल बनाने में संयोजक प्रभुनाथ मिश्रा, छटीलाल मिश्रा, राजेश द्विवेदी, राजकुमार जायसवाल एवं श्रीमती सत्या देवी जायसवाल सहित आयोजन समिति का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर इंद्रजीत सिंह छोटू ने सभी संयोजकों और आयोजन समिति का हृदय से आभार व्यक्त किया। कथा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के धर्मप्रेमी श्रद्धालु उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं।

10वीं में उत्कृष्ट सफलता, दर्शिता श्रीवास्तव को शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने दिया कंप्यूटर सेट

दुर्ग। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के शंकर नगर निवासी अश्वनी श्रीवास्तव की सुपुत्री कु. दशिर्ता श्रीवास्तव ने डीएवी हिंदी माध्यम स्कूल आर्यनगर, दुर्ग से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर आज गंजपारा स्थित कार्यालय में उन्हें शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कंप्यूटर सेट प्रदान कर सम्मान कर उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दिए। इस अवसर पर मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और निरंतर अध्ययन ही उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। सीमित संसाधनों के बीच भी यदि विद्यार्थी पूरे समर्पण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं।

कु. दशिर्ता श्रीवास्तव की सफलता को क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि आज के समय में शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है और विद्यार्थी देश एवं समाज का भविष्य हैं। प्रदेश सरकार भी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने लगातार कार्य कर रही है, ताकि हर छात्र-छात्रा अपने सपनों को पूरा कर सके। इस दौरान कु. दशिर्ता को आगे की पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन से जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किये और कहा की वे भविष्य में भी अपने माता-पिता, स्कूल और दुर्ग क्षेत्र का नाम रोशन करें। कार्यालय में उपस्थित लोगों ने भी कु. दशिर्ता श्रीवास्तव को उनकी सफलता पर बधाई दीं।

पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ाकर जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा रही : बाकलीवाल

कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

शहर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद से देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से लगातार जूझ रही है।

धीरज बाकलीवाल ने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव समाप्त होते ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि कर आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले पांच दिनों में दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। पहले तीन रुपये और अब 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिससे मार्च से अब तक पेट्रोल की कीमतों में लगभग छह रुपये और डीजल में चार रुपये तक की वृद्धि हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो गई है, जिसका सीधा असर खाद्य सामग्री एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर पड़ा है। रसोई से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बाकलीवाल ने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है, लेकिन भाजपा सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एवं राज्य की विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारें जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हुई हैं।

उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसान भी महंगाई और खाद संकट से परेशान हैं। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जबकि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर मौन बनी हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्ष 2014 में भाजपा नेताओं ने पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें कम करने का वादा किया था, लेकिन आज पेट्रोल के दाम दोगुने और रसोई गैस के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। धीरज बाकलीवाल ने मांग की कि प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर लगाए जा रहे 24 प्रतिशत वैट एवं अतिरिक्त टैक्स में कमी कर जनता को राहत दी जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ट्रिपल इंजन सरकार आम जनता को राहत देने में विफल रहती है, तो आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी।

सोसायटियों में खाद-बीज की किल्लत से किसान हो रहे परेशान - डॉ. प्रतीक उमरे

दुर्ग। नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे ने दुर्ग जिले की सहकारी समितियों एवं सोसायटियों में खाद, धान बीज और कृषि सामग्री की कमी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही जिले के किसान खेती-किसानी की तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन आवश्यक खाद एवं बीज समय पर उपलब्ध नहीं होने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा कि इस वर्ष मानसून समय से पहले दस्तक दे रहा है, जिसके कारण किसानों ने खेतों की तैयारी तेज कर दी है। किसान बड़ी उम्मीदों के साथ सहकारी सोसायटियों का रुख कर रहे हैं क्योंकि शासन की ओर से किसानों को रियायती दरों पर खाद और बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन वतर्मान स्थिति यह है कि अधिकांश सोसायटियों में खाद एवं बीज का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं है। किसानों की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने से किसान लगातार चक्कर काटने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी के अभाव का फायदा निजी दुकानदार उठा रहे हैं। मजबूरी में किसान निजी बाजार से महंगे दामों पर खाद एवं बीज खरीदने को विवश हैं। कई स्थानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूली जा रही है, जिससे किसानों का आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। किसानों की मजबूरी का कुछ व्यापारी अनुचित लाभ उठा रहे हैं और खाद-बीज की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है। डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा कि केवल महंगे दाम ही समस्या नहीं हैं, बल्कि बाजार में अमानक एवं घटिया गुणवत्ता वाले खाद और बीज भी बेचे जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा पर्याप्त जांच और निगरानी नहीं किए जाने के कारण नकली एवं निम्न गुणवत्ता के कृषि उत्पाद किसानों तक पहुंच रहे हैं। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका सीधा असर किसानों की फसल और धान उत्पादन पर पड़ेगा, जिससे भविष्य में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती के सीजन में समय पर खाद और बीज मिलना बेहद आवश्यक है। यदि शुरुआती दौर में ही किसानों को परेशानी होगी तो इसका असर पूरे कृषि चक्र पर पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए सभी सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराए साथ ही निजी बाजार में हो रही कालाबाजारी और अधिक मूल्य वसूली पर सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आग्रह किया की दुर्ग जिले की सभी सहकारी सोसायटियों में तत्काल पर्याप्त मात्रा में खाद एवं धान बीज उपलब्ध कराया जाए, प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाए तथा किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और खरीफ सीजन सुचारू रूप से संचालित हो सके।

भाजपा का जिला प्रशिक्षण महाअभियान 25-26 मई को, तैयारियों पर हुई बैठक

प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह करेंगे शुभारंभ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे समापन सत्र को संबोधित करेंगी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान के तहत 25 और 26 मई को जिला बालोद में होने वाले जिला प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में जिला प्रभारी रामजी भारती ने प्रशिक्षण वर्ग की रूपरेखा और कार्य विभाजन पर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।

संगठन मजबूती के लिए अहम -रामजी भारती

मुख्य वक्ता रामजी भारती ने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के वैचारिक विकास और संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने की अहम पहल है। शिविर का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, कार्यपद्धति और जनसंपर्क कौशल से सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि आगामी 36 घंटे हर कार्यकर्ता के व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

व्यवस्था के लिए समितियां गठित - देवांगन

जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग के संचालन के लिए मंच व्यवस्था, अतिथि स्वागत, भोजन, अनुशासन, तकनीकी सहयोग और मीडिया समन्वय की अलग समितियां बनाई गई हैं। सभी कार्यकर्ताओं से दायित्वों का निष्ठा से निर्वहन करने का आग्रह किया।

ये वक्ता रहेंगे मौजूद

प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह करेंगे। प्रमुख वक्ताओं में सांसद विजय बघेल, प्रदेश प्रशिक्षण संयोजक डॉ. अवधेश जैन, संजय श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, जगन्नाथ पाणिग्रही, प्रभुनाथ मिश्रा, महेश वर्मा, बृजेश भोजपुरिया समेत अन्य नेता शामिल होंगे। समापन सत्र को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे संबोधित करेंगी। विधायक डोमनलाल कोसेवाड़ा पूरे दो दिन प्रशिक्षण में मौजूद रहेंगे।

बैठक में जिला प्रभारी रामजी भारती, जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, विधायक डोमनलाल कोसेवाड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, प्रशिक्षण संयोजक गोपाल कृष्ण वर्मा, योगेंद्र सिंह, बृजेश भोजपुरिया, मनीष अग्रवाल, शैलेंद्र सिंह पदम, उषा बारले, भोजराज सिन्हा, दिव्या भसीन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

शिक्षकों ने डीईओ को सौंपा ज्ञापन, समस्याओं के निराकरण की मांग, 26 मई को होगी बैठक

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई-दुर्ग

शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द मिश्रा से मुलाकात कर स्थानीय समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ओम प्रकाश पाण्डेय और कमल वैष्णव ने किया।

प्रमुख मांगें रखीं

प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश में जनगणना कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए विशेष अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की मांग प्रमुखता से उठाई। इसके साथ ही डीडीओ स्तर पर शिविर लगाकर समयसीमा में सेवा पुस्तिका संधारण, सेवा पुस्तिका का कोष लेखा कार्यालय से परीक्षण, शिक्षकों की जीपीएफ पासबुक संधारित कराने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित मामलों का शीघ्र भुगतान करने की मांग रखी।

26 मई को होगी बैठक

जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि 26 मई को सभी संगठनों के जिलाध्यक्ष, तीनों विकासखंड शिक्षा अधिकारी और स्थापना शाखा के लिपिक की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें मांगों के निराकरण की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

ये रहे मौजूद

प्रतिनिधिमंडल में बी. प्रकाश, पवन सिंह, अमितेश तिवारी, राहुल झा, भोलाराम साहू सहित अन्य शिक्षक शामिल रहे।

मनरेगा मजदूरी भुगतान में तेजी, 23.39 करोड़ राशि श्रमिकों के खातों में जमा

कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश, रोजगार सहायकों को श्रमिकों से नियमित संपर्क बनाए रखने कहा

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत दुर्ग जिले में श्रमिकों की लंबित मजदूरी भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 23 करोड़ 39 लाख 17 हजार रुपये की मजदूरी राशि एसएनए-स्पर्श प्रणाली के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। वतर्मान में बड़ी संख्या में श्रमिकों के खातों में राशि सफलतापूर्वक जमा हो चुकी है तथा शेष भुगतान प्रक्रिया लगातार जारी है।

उन्होंने बताया कि शासन स्तर से प्राप्त राशि का प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न जनपद पंचायतों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। इसके अंतर्गत जनपद पंचायत दुर्ग में 8 करोड़ 64 लाख 68 हजार रुपये, जनपद पंचायत धमधा में 6 करोड़ 34 लाख 53 हजार रुपये तथा जनपद पंचायत पाटन में 6 करोड़ 25 लाख 67 हजार रुपये की राशि संबंधित श्रमिकों के खातों में जमा की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से 2 करोड़ 14 लाख 29 हजार रुपये की मजदूरी राशि का भी भुगतान किया जा चुका है।

सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि मनरेगा श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने जिले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, कार्यक्रम अधिकारियों, तकनीकी अमले एवं जनपद पंचायत स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मजदूरी भुगतान से जुड़ी खातों संबंधी समस्याओं, आधार सीडिंग, बैंकिंग त्रुटियों अथवा तकनीकी बाधाओं का तत्काल निराकरण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर श्रमिकों को उनके खातों में राशि जमा होने की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि भुगतान संबंधी भ्रम की स्थिति न बने। साथ ही रोजगार सहायकों को प्रतिदिन श्रमिकों से संपर्क बनाए रखने, भुगतान की स्थिति की जानकारी साझा करने तथा शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जिन श्रमिकों के खातों में तकनीकी अथवा बैंकिंग कारणों से भुगतान लंबित है, उनके मामलों की अलग से मॉनिटरिंग कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी भुगतान से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सतत निगरानी रखने कहा गया है, ताकि श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मनरेगा अंतर्गत मजदूरी भुगतान प्रक्रिया को लगातार गति प्रदान की जा रही है तथा सभी संबंधित विभागों और बैंकिंग संस्थाओं के समन्वय से लंबित भुगतान का निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

एमआरपी के नाम पर उपभोक्ता शोषण बर्दाश्त नहीं : अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा एमआरपी के नाम पर हो रहे उपभोक्ता शोषण, भ्रामक मूल्य निर्धारण, यूनिट सेल प्राइस नियमों के उल्लंघन तथा पैकेजिंग आधारित अत्यधिक वसूली के खिलाफ व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई है। संगठन ने कहा कि एमआरपी व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है, इसलिए मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता एवं छिपे शुल्कों पर सख्त निगरानी आवश्यक है।

जारी प्रेस विज्ञप्ति में संगठन ने कहा कि औषधियों, श्रृंगार प्रसाधनों, रेडीमेड वस्त्रों, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मॉल, एयरपोर्ट, अस्पतालों एवं अन्य सेवा स्थलों पर एमआरपी और वास्तविक वसूली के बीच बढ़ता अंतर उपभोक्ता हितों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। संगठन ने बताया कि Legal Metrology (Packaged Commodities) [illegible], 2011 के अनुसार एमआरपी सभी करों सहित निर्धारित होता है। साथ ही यूनिट सेल प्राइस, नेट क्वांटिटी, निर्माता, पैकर अथवा आयातक की जानकारी तथा उपभोक्ता सहायता संबंधी विवरण स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य रूप में प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि hidden charges, platform fee, convenience fee, packing fee अथवा service charge के नाम पर अतिरिक्त वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे मामलों में जिला एवं राज्य प्रशासन को औचक निरीक्षण, बिल सत्यापन तथा दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। संगठन ने कहा कि एमआरपी व्यवस्था केवल पैकेट पर छपी संख्या न रहकर उपभोक्ता सुरक्षा का प्रभावी माध्यम बननी चाहिए। इस अवसर पर रामपाल सिंह, अनुराग त्रिपाठी, आशीष गोस्वामी, वैभव तिवारी, लक्ष्मीकांत शर्मा तथा ओम प्रकाश पटेल उपस्थित रहे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, छत्तीसगढ़ प्रांत ने अंत में कहा कि एमआरपी, यूनिट सेल प्राइस एवं प्राइस ट्रांसपेरेंसी को लेकर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई समय की मांग है। संगठन इस विषय पर जन-जागरूकता, विधिक पहल एवं प्रशासनिक संवाद आगे भी जारी रखेगा।

छत्तीसगढ़ बना कृषि सुधारों का राष्ट्रीय मॉडल: मंत्री रामविचार नेताम

भुवनेश्वर जोनल कॉन्फ्रेंस में मंत्री रामविचार नेताम ने रखी राज्य की उपलब्धियां, केंद्र ने की सराहना

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 19 मई को आयोजित राष्ट्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ को कृषि नवाचार, किसान कल्याण और टिकाऊ खेती के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय वृद्धि, कृषि विविधीकरण और ग्रामीण समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने तिलहन मिशन के तहत पूर्वोत्तर पांच राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वारा लक्ष्य पूरा करने में पहले स्थान प्राप्त करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री श्री नेताम ने बताया कि राज्य में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में धान के लिए सबसे पारदर्शी और ऐतिहासिक समर्थन व्यवस्था मानी जा रही है। पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने 437 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी कर किसानों के खातों में लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये का सीधा भुगतान किया है।

भूमिहीन मजदूरों से लेकर डिजिटल खेती तक

सम्मेलन में मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार केवल बड़े किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत 5 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता सीधे बैंक खातों में दी जा रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ तेजी से बागवानी और वैकल्पिक खेती के केंद्र के रूप में उभर रहा है। बस्तर में कॉफी, अनासपाती और जशपुर में चाय की खेती आदिवासी क्षेत्रों में नई आर्थिक संभावनाएं खोल रही हैं।

कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने जोनल कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में 128 हाईटेक नर्सरी, 71 कोल्ड स्टोरेज, 63 पैकहाउस और 428 सोलर ड्रायर विकसित किए गए हैं। ऑयल पाम, बांस मिशन, प्राकृतिक खेती, दलहन-तिलहन विस्तार तथा कृषि वानिकी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 4.89 लाख किसानों को 854 करोड़ रुपये से अधिक की दावा राशि वितरित की गई है। श्री परदेशी ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में एआई, ड्रोन तकनीक और एकीकृत किसान पोटलों के माध्यम से कृषि व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने की छत्तीसगढ़ की सराहना

राष्ट्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीस्टेक पोर्टल, दलहन-तिलहन विस्तार, पीएम आशा योजना, प्राकृतिक खेती और तिलहन मिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की। उन्होंने पूर्वोत्तर एवं पूर्वी भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के बीच तिलहन मिशन में लक्ष्य प्राप्ति पर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान हासिल करने के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर 5 राज्यों के कृषि मंत्री सहित छत्तीसगढ़ शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं विभागीय सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक कृषि राहुल देव, संचालक उद्यानिकी लोकेश चन्द्राकर और संयुक्त संचालक कृषि गयाराम उपस्थित थे।

खास खबर

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की मुलाकात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राजनांदगांव स्थित उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के समग्र विकास, सुशासन, वित्तीय प्रबंधन तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के लंबे प्रशासनिक अनुभव एवं मार्गदर्शन को राज्य के विकास के लिए प्रेरणादायी बताया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मंत्री राजवाड़े की पहल से सिलफिली मंडी को मिली बड़ी राहत, औचक निरीक्षण के दौरान मिली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई

रायपुर। आमजन की सुविधाओं और स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उनके निर्देश पर सिलफिली सब्जी मंडी में वर्षों से लंबित ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग की समस्या का स्थायी समाधान कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों और नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।

गौरतलब है कि 10 मई को मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सिलफिली सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने उन्हें ट्रांसफार्मर की अनुचित स्थिति, आवागमन में हो रही परेशानी तथा सार्वजनिक शौचालय के संचालन संबंधी समस्याओं से अवगत कराया था। मंत्री ने मौके पर ही समस्या का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

सिलफिली सब्जी मंडी परिसर में ट्रांसफार्मर लंबे समय से ऐसे स्थान पर स्थापित था, जहां व्यापारियों, ग्राहकों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी के साथ सुरक्षा संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ता था। मंत्री श्रीमती राजवाड़े के निर्देश के बाद बिजली विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर को सुरक्षित और उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया। इससे मंडी परिसर में आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित हो गया है तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी सुविधा मिली है।

इसी क्रम में मंत्री श्रीमती राजवाड़े की पहल पर मंडी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक शौचालय को भी व्यवस्थित रूप से संचालित कराया गया। इससे व्यापारियों, महिलाओं एवं आम नागरिकों को स्वच्छ और सुविधाजनक मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सकी है। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने इस पहल को जनहित में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय लेने की कार्यशैली से क्षेत्रवासियों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने विस भवन का किया निरीक्षण, पेपरलेस करने के कार्यों में आएगी तेजी

पर्याप्त पार्किंग के साथ सर्वसुविधायुक्त ड्राइवर-रूम बनाने के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन लोकभवन (राजभवन) के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण कर ले-आउट और फ्लोर-प्लान जाना। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री बंसल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए तकनीकी कार्यों और व्यवस्थाओं में तेजी लाने लोक निर्माण विभाग और चिप्स को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी, अपर सचिव एसएन श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता टीआर कुंजाम, अधीक्षण अभियंता डीके नेताम और कार्यपालन अभियंता अभिनव श्रीवास्तव भी इस दौरान मौजूद थे।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने लोकभवन का निर्माण राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप उत्कृष्टता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरे परिसर के सौंदर्य, सूरज की रोशनी और पूर्ण उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने भवन की सभी बारीकियों पर पुख्ता काम करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कार्यक्रमों के आयोजन के लिए यहां बन रहे सभा-भवनों और कार्यालयीन कक्षों की बैठक व्यवस्था पहले से ही निर्धारित कर उनके अनुरूप कार्यों को अंजाम देने को कहा। उन्होंने भवन के निर्माण कार्य में लगे अलग-अलग एजेंसियों से कार्य प्रगति की जानकारी लेकर यथाशीघ्र सभी कार्य पूर्ण कर इसे लोक निर्माण विभाग को हैंड-ओवर करने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री बंसल ने नए विधानसभा भवन में प्रवेश द्वार, सदन, अधिकारी दीर्घा, लॉबी, डाइनिंग एरिया, मीडिया ब्रीफिंग एरिया, समिति कक्ष, मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय, उप मुख्यमंत्रियों तथा मंत्रियों के कार्यालयों, ऑफिसर लाउंज और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के कार्यालयों का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कार्यालयीन कक्षों में समुचित फर्नीचर और बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए भवन में वर्तमान व्यवस्था की कमियों और खामियों को आगामी मानसून सत्र के पहले दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

विधानीय सचिव ने विधानसभा को पेपरलेस करने तकनीकी व्यवस्थाओं को तेजी से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और चिप्स के अधिकारियों के साथ इसके लिए जरूरी इंतजामों, उपकरणों, हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स की भी समीक्षा की। उन्होंने बेहतर समन्वय और तेजी से काम करते हुए इस साल के शीतकालीन सत्र तक सभी तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर पखवाड़े इसकी प्रगति की समीक्षा करने भी कहा।

श्री बंसल ने विधानसभा परिसर में गाड़ियों के पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था के साथ वाहन चालकों के लिए सर्वसुविधायुक्त कक्ष भी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार क्रमांक-3 में पास-काउंटर के पास आगंतुकों के लिए बनने वाले प्रतीक्षालय कक्ष के साथ ही विधानसभा ड्यूटी करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए कैन्टीन बनाने का भी सुझाव दिया।

स्टेशन पर टिकट चेकिंग : 528 से वसूले 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना

26 ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले 409 यात्री पकड़े गए

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी के निर्देश पर गुरूवार को रायपुर मंडल में रायपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें रायपुर स्टेशन के सभी प्लेटफार्म, 26 ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले 409 यात्री पकड़े गए। जिससे 2,78,135 रुपए राजस्व प्राप्त हुआ। अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वाले 74 यात्रियों से 34,115 रुपए रुपए राजस्व प्राप्त हुआ, अधिक लगेज लेकर यात्रा करने वाले 10 यात्रियों से 2500 रुपए राजस्व प्राप्त हुआ और रेलवे स्टेशन पर कचरा फैलाने वाले 35 यात्रियों से 3700 रुपए राजस्व प्राप्त हुआ ।

इस टिकट चेकिंग अभियान में कुल 528 मामलों को दर्ज कर 3,18,450 रुपए राजस्व प्राप्त किया गया। इस टिकट चेकिंग का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को टिकट लेने के प्रति जागरूक करना था। इस टिकट चेकिंग अभियान का संचालन सहायक वाणिज्य प्रबंधक अविनाश कुमार आनंद के द्वारा एवं 1 मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, 2 वाणिज्य निरीक्षक, 4 वाणिज्य कार्यालय के स्टाफ, 24 टिकट चेकिंग स्टाफ, 02 आरपीएफ स्टाफ शामिल रहे।

रेल प्रशासन यात्रियों को आगाह करता है कि वे यात्रा हेतु उचित टिकट एवं रेल परिसर में प्रवेश करने के पहले प्लेटफॉर्म टिकट अवश्य खरीदें। रेलगाड़ी एवं रेल परिसर को साफ सुथरा रखने में भी रेल प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ।जिससे यात्रियों को टिकट लेने के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है, साथ ही यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है कि वे उचित टिकट लेकर सही कोच में बैठे एवं अपनी सुखद यात्रा करें एवं टिकट चेकिंग में रेलवे प्रशासन को सहयोग करें।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव प्रथम तेलीन सत्ती माता महोत्सव में हुए शामिल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोण्डागांव जिले के केशकाल में साहू संघ बस्तर संभाग द्वारा आयोजित प्रथम तेलीन सत्ती माता महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप और भोजराज, विधायक नीलकंठ टेकाम और आशाराम नेताम सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं समाज के प्रमुखजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने तेलीन सत्ती माता को नमन करते हुए महोत्सव के प्रथम आयोजन पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि केशकाल घाटी से गुजरने वाले यात्री तेलीन सत्ती माता का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिससे उनकी यात्रा सफल और मंगलमय होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में यह महोत्सव और अधिक

भव्य स्वरूप में आयोजित होगा तथा सभी के सहयोग से इसका गौरव लगातार बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के गौरव हैं और उनके नेतृत्व में गांव, गरीब एवं किसानों के कल्याण के लिए अनेक जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि साहू समाज अन्य समाजों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ महतारी के गौरव को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यहां मां दंतेश्वरी की आराधना के लिए देशभर से लोग एकत्रित होते हैं। उन्होंने समाज के लोगों से एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक बस्तर संभाग को विकसित संभाग बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें जनसहयोग आवश्यक है।

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने समाज को विभाजित करने वाली ताकतों से सतर्क रहने और सभी समाजों को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने भी महोत्सव के सफल आयोजन पर शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष जितेंद्र साहू, पूर्व मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, ताम्रध्वज साहू, कमलचंद भंजदेव, पूर्व सांसद दीपक बैज, साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू और महोत्सव समिति के संयोजक राजेश मायाराम साहू सहित साहू समाज के अनेक पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

कुसुमताल शिविर में हितग्राहियों को मिली खुशियों की सौगात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जशपुर जिले में आमजन को शासन की विभिन्न योजनाओं का लगातार लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में जशपुर जिले के जनपद पंचायत कांसाबेल अंतर्गत ग्राम पंचायत कुसुमताल में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को उनके पक्के घर के सपने को साकार करने हेतु खुशियों की चाबी प्रदान की गई। वहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों को पेंशन प्रमाण पत्र वितरित किए गए। दिव्यांग हितग्राहियों को भी विशेष रूप से लाभान्वित किया गया। शिविर में एक दिव्यांग हितग्राही को सहायक उपकरण के रूप में व्हीलचेयर प्रदान की गई, जिससे उनके दैनिक जीवन की गतिविधियों में सुविधा होगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। योजनाओं का लाभ मिलने से हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरिता भगत, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती हीरामती पैंकरा, वरिष्ठ नागरिक सुदाम पांडा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से ग्रामीणों को उनके गांव के समीप ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

शिविर के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उपस्थित ग्रामीणों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। सभी ने नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। ग्रामीणों ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से उन्हें योजनाओं का लाभ घर के पास ही मिल रहा है, जिससे समय, धन और श्रम की बचत हो रही है। यह पहल न केवल समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बन रही है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

बायसन के हमले से एक ग्रामीण की मृत्यु वन विभाग ने की गई तत्काल सहायता

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

वन विकास निगम परियोजना परिक्षेत्र रवान अंतर्गत मंगलवार को तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए जंगल गए ग्रामीणों पर बायसन के हमले में एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बलौदा बाजार की वन विभाग टीम एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई। परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी रवान द्वारा मृतक के परिजनों को तात्कालिक सहायता राशि 25,000 प्रदान की गई है। साथ ही शासन के प्रावधान अनुसार मृतक के परिवार को देय क्षतिपूर्ति राशि भी प्रदान की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बायसन के हमले में तीन ग्रामीण घायल हो गये।

इस घटना में ग्राम गजराडीह निवासीदेवेन्द्र साहू (उम्र 45 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। घटना में घायल अन्य दो ग्रामीणों का निजी अस्पताल में उपचार जारी है। वनमण्डलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने कहा है कि वन विभाग द्वारा लगातार ग्रामीणों को मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से बचाव के संबंध में जागरूक किया जा रहा है तथा वन क्षेत्रों में सुरक्षा एवं सतकर्ता बनाए रखने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वन क्षेत्रों में जाते समय सावधानी बरतें एवं वन विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

संपादकीय

जन-सुरक्षा व पशु-कल्याण के बीच हो संतुलन

कोर्ट की सख्ती के मायने

इसमें दो राय नहीं कि स्थानीय निकायों द्वारा आवारा कुत्तों को हटाने के संबंध में विगत में दिए अपने निर्देशों को नरम न करने का सवोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, बिगड़ते जन-सुरक्षा संकट में एक आवश्यक हस्तक्षेप है। हाल के वर्षों में, देश भर में स्थानीय प्रशासन व निकाय कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार हो रही चिंताजनक वृद्धि को रोकने में विफल ही रहे हैं। ऐसे में शासन व प्रशासन स्तर पर इस समस्या के निराकरण की कोई सार्थक पहल न होते देख ही, शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा है।

नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार, साल 2023 में तीस लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए थे। उसके अगले साल 2024 में रोकथाम के कोई ठोस प्रयास न होने के कारण 37 लाख मामले दर्ज किए गए। आंकड़े बता रहे हैं कि औसतन प्रतिदिन दस हजार घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं कई राज्यों व शहरों में इन घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। हाल ही में सामने आए केरल के आंकड़ों के अनुसार, वहां एक साल के भीतर ही 3.6 लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी दिल्ली से सटे नोएडा में कुछ ही महीनों में हजारों शिकायतों के बाद हॉटस्पॉट की पहचान की गई।

इन शिकायतों में स्कूलों के पास उनका जमावड़ा होना, चलने में असमर्थ बुजुर्ग नागरिकों का शिकार बनना व आम नागरिकों के आवारा कुत्तों के भय में जीने के मामले उजागर हुए हैं। दरअसल, विगत में भी इस संकट के कारगर समाधान के लिये शीर्ष अदालत ने सख्त निर्देश दिए थे। स्थानीय नगर निगम व नगर पालिकाओं की जवाबदेही तय की थी कि कुत्तों को शेल्टर होम ले जाकर उनकी नसबंदी की जाए और टीकाकरण किया जाए। लेकिन इस दिशा में कारगर पहल होती नजर नहीं आई। वहीं तसवीर का दूसरा पहलू है कि यह संकट समाज और संस्थाओं द्वारा जानवरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार में परेशान करने वाली विफलता को भी दर्शाता है।

पिछले दिनों चंडीगढ़ से एक स्तब्धकारी घटना ने हर किसी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित किया,जब एक अज्ञात व्यक्ति ने एक पिल्ले को धधकते तंदूर में फेंककर जिंदा जला दिया। ऐसे शमर्नाक कृत्य उस भयावह क्रूरता को उजागर करते हैं, जो सार्वजनिक चर्चाओं में उजागर नहीं होती। इस घटना ने इन जीवों की दयनीय स्थिति को ही उजागर किया। वहीं भूख से बिलबिलाते कुत्तों द्वारा कथित तौर पर अपने ही बच्चों को खाने के मामले भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी से सहमत हुआ जा सकता है कि जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार का मतलब नागरिकों की सुरक्षा की अनदेखी करना नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ ही जन सुरक्षा को पशु कल्याण की उपेक्षा का बहाना भी नहीं बनाया जा सकता है।

निस्संदेह, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनी रूप से जानवरों को स्थानांतरित करने पर दिए गए जोर के साथ अब आश्रय स्थलों, नसबंदी केंद्रों, टीकाकरण अभियानों और पशु चिकित्सा सुविधाओं में अधिक निवेश करने की सख्त जरूरत है। निश्चय ही यह चुनौती एक जटिल विषय है। सही मायनों में चुनौती यह भी है कि एक मानवीय, जवाबदेह और प्रभावी आवारा पशु प्रबंधन व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जो नागरिकों और कुत्तों , दोनों के हितों की रक्षा कर सके। हमेशा से ही कुत्ते की गिनती मनुष्य के वफादार साथी के रूप में की जाती रही है। सदियों से दोनों एक साथ रहे हैं। उन कारणों की भी पड़ताल की जानी चाहिए, जिनके चलते कुत्ते अचानक आक्रामक व्यवहार दिखाने लगे हैं। निश्चय ही बढ़ता तापमान बदलते मौसमों के प्रति संवेदनशील इन जीवों को बेचैन किए हुए है। भूख व आश्रय के अभाव से उपजे असुरक्षाबोध ने भी उन्हें आक्रामक बनाने में भूमिका निभायी है। ऐसे में पशु प्रेमी संगठनों और स्थानीय प्रशासन को मिलकर इस संकट का कारगर समाधान निकालना होगा। ये समाधान सिर्फ सरकार या स्थानीय निकायों के बूते होना संभव नहीं है। पशु प्रेमियों की बड़ी पहल के परिणाम बदलाव लाने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

वायरस : हंतावायरस-इबोला से फिर दी स्वास्थ्य को चुनौती

मुकुल व्यास

कांगो में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस ने चिंता बढ़ा दी है क्योंकि वहां युद्ध की वजह से संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल है। इबोला की प्रजाति भी दुर्लभ है जिसे रोकने के लिए कम ही साधन हैं। वायरस संक्रमित लोगों में से एक-तिहाई लोगों की जान ले लेता है। वहीं हंतावायरस की नई चुनौती भी है।

कुछ दिन पहले एक क्रूज जहाज, एमवी होंडियस पर हंतावायरस के मामलों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए नई चिंता पैदा कर रहा है। यह वायरस हफ्तों से दुनिया के एक ऐसे हिस्से में फैल रहा है, जहां गृह युद्ध की वजह से संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल है। साथ ही, इसमें शामिल इबोला की प्रजाति भी दुर्लभ है। इसलिए इस वायरस को रोकने के लिए अधिकारियों के पास कम ही साधन उपलब्ध हैं। यह वायरस संक्रमित लोगों में से लगभग एक-तिहाई लोगों की जान ले लेता है। यह इस महामारी के फैलने का एक बहुत ही नाजुक दौर है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक प्रतिनिधि ऐन एन्सिया ने चेतावनी दी है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप, जिसने कम से कम 131 लोगों की जान ले ली है, शायद मूल अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। डॉ. एन्सिया ने बताया कि जांच से यह और भी साफ होता जा रहा है कि यह बीमारी दूसरे इलाकों में भी फैल चुकी है। अभी तक डीआर कांगो में 513 से ज्यादा मामलों का संदेह है, जबकि पड़ोसी देश युगांडा में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। लंदन स्थित एमआरसी सेंटर फॉर ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीज एनालिसिस द्वारा जारी किए गए एक मॉडल के अनुसार, इबोला के बहुत से मामले पकड़ में नहीं आए हैं, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मामलों की संख्या 1,000 से अधिक है।

दरअसल, मौजूदा प्रकोप जितना अभी दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और इसका असली दायरा अभी भी अनिश्चित है। 6 अमेरिकी नागरिकों के वायरस के संपर्क में आने की सूचना मिली है। इबोला के अधिकतर मामले छोटे स्तर के ही होते हैं, लेकिन

विशेषज्ञ 2014-16 में फैली महामारी को याद करके नए प्रकोप पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। उस समय पश्चिम अफ्रीका में इबोला के सबसे बड़े प्रकोप के दौरान 28,600 लोग संक्रमित हुए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित किया है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम कोविड जैसी किसी बड़ी महामारी के शुरुआती दौर में पहुंच गए हैं।

पूरी दुनिया के लिए इबोला से होने वाला खतरा अब भी कम है। वर्ष 2014-16 में इबोला महामारी के दौरान भी ब्रिटेन में इबोला के केवल तीन मामले सामने आए थे, और वे सभी स्वास्थ्यकर्मी थे जो स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए थे। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के पैंडेमिक साइंसेज इंस्टिट्यूट की वैज्ञानिक डॉ. अमांडा रोजेक का कहना है कि नए प्रकोप पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी तालमेल की जरूरत है। युगांडा, दक्षिण सूडान और रवांडा जैसे पड़ोसी देशों के लिए यह इबोला अब भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इन देशों को व्यापार और यात्रा के घनिष्ठ संबंधों के कारण उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। इबोला एक गंभीर और जानलेवा संक्रामक बीमारी है।

दरअसल, इबोला वायरस स्वाभाविक रूप से जानवरों, मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन अगर लोग उनके सीधे संपर्क में आते हैं, तो वे भी संक्रमित हो सकते हैं। इस प्रकोप का कारण इबोला वायरस की बुंडिबुग्यो प्रजाति है। यह उन तीन प्रजातियों में से एक है, जिनके कारण संक्रमण फैलता है। बुंडिबुग्यो ने पहले केवल दो बार प्रकोप फैलाया है। वर्ष 2007 और 2012 में इसने संक्रमित लोगों में से लगभग 30 प्रतिशत की जान ले ली थी। बुंडिबुग्यो वायरस स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष कई तरह की चुनौतियां खड़ी करता है।

इबोला वायरस की अन्य प्रजातियों के विपरीत बुंडिबुग्यो के लिए कोई भी स्वीकृत टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ प्रायोगिक दवाएं अवश्य मौजूद हैं। वायरस के संक्रमण की पुष्टि करने वाले टेस्ट बहुत कारगर नहीं हैं। इस प्रकोप के शुरुआती नतीजे इबोला वायरस के लिए नेगेटिव आए थे और वायरस की पुष्टि करने के लिए अधिक उन्नत प्रयोगशाला उपकरणों की आवश्यकता पड़ी। इसमें बुंडिबुग्यो भी शामिल है। ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ट्रूडी लैंग कहती हैं कि बुंडिबुग्यो से निपटना इस प्रकोप में एक बहुत बड़ी चिंता है।

समझा जाता है कि संक्रमण होने के दो से 21 दिनों के भीतर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में ये फ्लू के लक्षणों जैसे होते हैं जिनमें बुखार, सिरदर्द और थकान शामिल हैं। लेकिन जैसे-जैसे इबोला बढ़ता है, इससे उल्टी, दस्त और शरीर के अंगों का काम करना बंद हो जाना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कुछ मरीजों को शरीर के अंदर और बाहर रक्तस्राव की समस्या भी हो जाती है। बुंडिबुग्यो वायरस को सीधे निशाना बनाने के लिए कोई भी स्वीकृत दवा उपलब्ध न होने के कारण इसका इलाज बेहतर सहायक देखभाल पर निर्भर करता है, जिसमें दर्द, अन्य संक्रमणों, शरीर में तरल पदार्थों और पोषण का प्रबंधन शामिल है। शुरुआती देखभाल से मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है।

अफ्रीका में इबोला के मामले सामने आने से कुछ दिन पहले एक क्रूज जहाज पर कुछ यात्रियों के हंतावायरस के संक्रमित लोगों की खबर ने कोविड के दिनों की याद ताजा कर दी। छह साल पहले, मार्च 2020 में एक क्रूज जहाज रूबी प्रिंसेस के सिडनी में डॉक होने के बाद कोविड फैल गया था। जहाज से उतरे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 575 लोग कोविड से संक्रमित थे। इसके बाद यह वायरस और दूसरे लोगों में भी फैल गया। अतः अब एमवी होंडियस जहाज पर हंतावायरस की मौजूदगी पर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तत्काल सावधानी बरतना और क्वारंटीन जैसे कदम उठाना स्वाभाविक था।

होंडियस के यात्री एंडीज वायरस के संपर्क में आए जो कि एक प्रकार का हंतावायरस है जो चूहों से फैलता है। एंडीज वायरस एक खतरनाक वायरस है लेकिन कोविड के साथ इसकी तुलना कुछ हद तक ही की जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अनेक विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस में वे विशेषताएं नहीं हैं जो इसे अगला कोविड बना सकें। हंतावायरस एक ऐसा वायरस समूह है जो आमतौर पर चूहों, गिलहरियों और चूहों जैसी अन्य प्रजातियों (रोडेंट) द्वारा फैलाया जाता है। ज्यादातर हंतावायरस के बारे में यह नहीं मालूम है कि वे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं या नहीं। लेकिन एंडीज वायरस इसका अपवाद है। संक्रमित चूहों से इंसानों में फैलने के बाद यह एकमात्र ऐसा हंतावायरस है जिसके एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के पुष्ट प्रमाण मौजूद हैं।

चुनावी तंत्र में भरोसा कायम रखने की चुनौती

दिनेश भारद्वाज

एसआईआर का तीसरा चरण केवल वोटर लिस्ट सुधार कार्यक्रम नहीं। यह भारत के लोकतंत्र की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और राजनीतिक दलों की परिपक्व्ता की एक साथ परीक्षा है। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शी, संतुलित और निष्पक्ष तरीके से पूरी होती है तो भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होकर उभरेगा।

भारत में चुनाव केवल सरकार बदलने की प्रक्रिया नहीं होते, वे लोकतंत्र की सामूहिक वैधता का उत्सव भी होते हैं। लेकिन जब मतदाता सूची ही सवालों के घेरे में आ जाए, तब लोकतंत्र की पूरी संरचना बहस के केंद्र में आ खड़ी होती है। यही वजह है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का तीसरा चरण केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का संवेदनशील अध्याय बन गया है।

निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर लागू करने का कार्यक्रम घोषित किया है। इनमें ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं, जबकि केंद्रशासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, तथा चंडीगढ़ को शामिल किया गया है। इनमें से कई राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को केवल ह्यमतदाता सूची सुधार अभियानह्न मानकर नहीं देखा जाएगा। इसके राजनीतिक अर्थ, चुनावी प्रभाव व लोकतांत्रिक संकेत दूरगामी होंगे।

चुनाव आयोग का तर्क है कि इस मुहिम का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। मृत मतदाताओं के नाम हटाने हैं, डुप्लीकेट वोट समाप्त करने हैं, माइग्रेशन के कारण बदले पते अपडेट करने हैं और नए पात्र मतदाता जोड़ने हैं। सिद्धांततः इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति केवल सिद्धांतों से नहीं; आशंकाओं व अनुभवों से भी संचालित होती है। ऐसे में एसआईआर तकनीकी प्रक्रिया कम और राजनीतिक बहस अधिक बन चुका है।

बीते कुछ वर्षों में बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मतदाता सूची को लेकर विवाद उठते रहे हैं। विपक्षी दल आरोप लगाते रहे कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं या फिर चुनावी लाभ के लिए वोटर लिस्ट में ह्यमैनेजमेंटह्न किया जा रहा है। हाल में पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद यह बहस और तेज हो गई। विपक्ष का आरोप है, चुनावी प्रक्रिया में अपेक्षित पारदर्शिता नहीं।

दूसरी ओर केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल इन आरोपों को राजनीतिक हार की हताशा बताते हैं। यानी मतदाता सूची अब केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं रही; राजनीतिक विश्वास और अविश्वास की कसौटी बन चुकी है। यहीं बड़ा सवाल है कि क्या एसआईआर वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने की निष्पक्ष प्रक्रिया है, या फिर राजनीति के ध्रुवीकरण में यह भी नया सियासी औजार बनता जा रहा है?

सैद्धांतिक रूप से देखें तो एसआईआर की जरूरत है। इस विशाल देश में लगातार माइग्रेशन, शहरीकरण और जनसंख्या गतिशीलता के कारण मतदाता सूची को अद्यतन रखना बेहद कठिन कार्य है। करोड़ों लोग रोजगार, शिक्षा और सामाजिक कारणों से लगातार स्थान बदलते हैं। लाखों लोग मृत्यु के बाद भी वर्षों तक वोटर लिस्ट में बने रहते हैं। डुप्लीकेट वोट भी हैं। यदि निर्वाचन आयोग समय-समय पर व्यापक पुनरीक्षण न करे तो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता कमजोर पड़ सकती है। लेकिन विपक्ष का आरोप है, सत्यापन प्रक्रिया कई बार चयनात्मक दिखाई देती है। खासकर गरीब, प्रवासी, किरायेदार और हाशिये पर खड़े वर्गों के मतदाता सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जिन लोगों के पास स्थायी दस्तावेज नहीं, बार-बार पता बदलता है, या जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक आसानी से नहीं पहुंच पाते, वे सबसे पहले सूची से बाहर होते हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग दुनिया की सबसे विश्वसनीय चुनावी संस्थाओं में गिना जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। ऐसे में एसआईआर उसके लिए भी बड़ी परीक्षा है। ऐसे में निष्पक्ष होने के साथ ही निष्पक्ष दिखना भी जरूरी होगा। यदि लाखों मतदाताओं के नाम कटते हैं तो आयोग को पारदर्शी तरीके से यह बताना होगा कि किन आधारों पर कार्रवाई हुई।

लगभग सभी राजनीतिक दल सिद्धांततः ह्यशुद्ध मतदाता सूचीह्न के पक्ष में हैं, लेकिन व्यवहार में हर दल की चिंता अपने वोट बैंक को लेकर है। यदि किसी राज्य में बड़ी संख्या में शहरी प्रवासी मतदाता सूची से बाहर होते हैं तो इसका प्रभाव अलग होगा। ग्रामीण इलाकों में नाम कटते हैं तो समीकरण अलग होंगे। यदि नए युवा मतदाता बड़ी संख्या में जुड़ते हैं तो चुनावी रुझान बदल सकते हैं। यानी एसआईआर चुनावी गणित का भी बड़ा कारक है। यही वजह है कि सभी दल बूथ स्तर तक अपने बीएलए सक्रिय कर रहे हैं ताकि उसका समर्थक वोटर सूची में बना रहे और विरोधी पक्ष की संभावित ह्यगड़बड़ियांह्न पकड़ी जाएं।

देश में मतदाता सूची भी राजनीतिक युद्ध का मैदान बन चुकी है। बहस का मूल प्रश्न एसआईआर का होना या नहीं होना नहीं, बल्कि यह है कि क्या भारत की चुनावी प्रणाली आम नागरिक में भरोसा पैदा कर पा रही है? जब कोई मतदाता यह महसूस करने लगे कि उसका वोट सुरक्षित नहीं है या चुनावी प्रक्रिया पर राजनीतिक प्रभाव है, तब लोकतंत्र केवल संवैधानिक ढांचा भर रह जाता है। चुनाव आयोग की भूमिका लोकतांत्रिक विश्वास की संरक्षक संस्था की भी है। इसलिए एसआईआर प्रक्रिया संदेहों से ऊपर उठाकर संचालित करना उसकी अहम जिम्मेदारी होगी। एसआईआर का तीसरा चरण केवल वोटर लिस्ट सुधार कार्यक्रम नहीं। यह भारत के लोकतंत्र की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और राजनीतिक दलों की परिपक्व्ता की एक साथ परीक्षा है। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शी, संतुलित और निष्पक्ष तरीके से पूरी होती है तो भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होकर उभरेगा।

भारत-इटली संबंध : इंडो-भूमध्यसागरीय क्षेत्र के लिए एक रणनीतिक साझेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी - जॉर्जिया मेलोनी

हमारा लक्ष्य 2029 तक भारत व इटली के बीच व्यापार को 20 अरब यूरो से आगे ले जाना है। इसमें रक्षा एवं एयरोस्पेस, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पुर्जे, रसायन, दवाइयां, वस्त्र, कृषि-खाद्य क्षेत्र और पर्यटन आदि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा। भारत और इटली के संबंध अब निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं। हाल के वर्षों में इन रिश्तों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। यह संबंध केवल सौहादर्पूर्ण मित्रता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब स्वतंत्रता-लोकतंत्र के मूल्यों तथा भविष्य के साझा दृष्टिकोण आधारित एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। बदलाव के दौर से गुजरती दुनिया में इटली व भारत की साझेदारी उच्च राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर लगातार संवाद से आगे बढ़ रही है। यह संबंध अब उस व्यापक स्तर पर पहुंच रहा है, जिसमें दोनों की आर्थिक ताकत, सामाजिक रचनात्मकता और हजारों वर्षों की सभ्यतागत विरासत शामिल है।

हमारा सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि-सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि देश कितनी क्षमता से नवाचार करें, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करें और अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करें। इसी उद्देश्य से हमने विपक्षीय संबंधों को और गहरा बनाने का संकल्प लिया है, ताकि बेहतर उपयोग हो सके। हम इटली की डिजाइन क्षमता, विनिर्माण कौशल और विश्वस्तरीय सुपरकंप्यूटर तकनीक—जो उसे एक औद्योगिक महाशक्ति बनाती है—को भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, इंजीनियरिंग प्रतिभा, व्यापक क्षमता, नवाचार और 100 से अधिक यूनिकॉर्न तथा 2 लाख स्टार्ट-अप वाले उद्यमी इकोसिस्टम के साथ जोड़कर शक्तिशाली तालमेल बनाना चाहते हैं। यह ऐसा साझा मूल्य निर्माण है, जिसमें दोनों

देशों की औद्योगिक ताकतें एक-दूसरे को अधिक मजबूत बनाती हैं।

यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दोनों दिशाओं में व्यापार व निवेश बढ़ाने का रास्ता खोलता है। हमारा लक्ष्य 2029 तक भारत व इटली के बीच व्यापार को 20 अरब यूरो से आगे ले जाना है। इसमें रक्षा एवं एयरोस्पेस, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पुर्जे, रसायन, दवाइयां, वस्त्र, कृषि-खाद्य क्षेत्र और पर्यटन आदि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा। उत्कृष्टता का प्रतीक ह्यमेड इन इटलीह्न और आज इसका स्वाभाविक तालमेल ह्यमेक इन इंडियाह्न पहल के उच्च गुणवत्ता वाले लक्ष्यों के साथ दिखाई देता है। इसी संदर्भ में, भारत के लिए उत्पादन में इतालवी कंपनियों की बढ़ती रुचि व इटली में भारतीय उद्योगों की बढ़ती मौजूदगी, जो अब दोनों पक्षों को मिलाकर 1000 से अधिक हो चुकी है, सकारात्मक संकेत है। यह सप्लाई चेन के एकीकरण को मजबूत करेगी।

तकनीकी नवाचार हमारी साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। आने वाले दशकों में दुनिया बड़े तकनीकी बदलाव के दौर से गुजरेगी, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी। भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र, कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता—इन क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक बनाती है। दोनों देशों के वि.वि. शोध संस्थानों के बीच बढ़ती साझेदारी इसे मजबूती देगी।

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पहले से ही दुनिया के कई देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। विशेष रूप से एआई आज हमारे समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रही है। इटली और भारत सहयोग कर रहे हैं, ताकि एआई का विकास जिम्मेदार और मानव-केंद्रित हो।

भारत-इटली एआई को समावेशी विकास का सशक्त माध्यम मानते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सरल, बहुभाषी तकनीकों के माध्यम से एआई सामाजिक और डिजिटल खाइयों को कम कर सकता है। भारत के मानव विजन यानी तकनीक के केंद्र में मानव को रखने की सोच और इटली की मानव-केंद्रित ह्यएल्गोर-एथिक्सह्न की अवधारणा, जो मानवतावादी परंपरा पर आधारित है, पर आगे बढ़ते हुए हमारी साझेदारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई सामाजिक सशक्तीकरण का माध्यम बने। हमारा दृष्टिकोण भारत की विशाल डिजिटल क्षमता को इटली की नैतिक और औद्योगिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है, ताकि तकनीक मानव गरिमा की सेवा कर सके।

सुरक्षित डिजिटल सहयोग, क्षमता निर्माण और मजबूत साइबर ढांचे से जुड़ी श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करके, हम एक ऐसा खुला, भरोसेमंद और समान डिजिटल वातावरण बनाना चाहते हैं, जिसमें हर देश एआई का उपयोग कर सके और उससे लाभ उठा सके। यही सोच इटली की जी-7 अध्यक्षता और 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के निष्कर्षों का मुख्य आधार है। यह बताना कि तकनीक न तो मनुष्य की जगह ले सकती है और न ही उसके मूल अधिकारों को कमजोर कर सकती है। इसका उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप हेतु न हो।

अंतरिक्ष अनुसंधान और सैटेलाइट तकनीक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति तथा इटली की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता, संयुक्त परियोजनाओं और नई पीढ़ी की तकनीकों के विकास के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। इटली और भारत रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक तकनीकों आदि में सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं। हमारा सहयोग महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध व मानव तस्करी जैसी चुनौतियों के खिलाफ मजबूती बढ़ाएगा।

दुनिया में ऊर्जा के विविध स्रोतों की ओर बढ़ रहे बदलाव के लिए नवाचार, निवेश और सहयोग की आवश्यकता है। भारत और इटली नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर हाइड्रोजन तकनीक व स्मार्ट ग्रिड से लेकर मजबूत बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनने की भारत की पहल अपार संभावनाएं रखती है। यह इटली की नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना में उन्नत तकनीक और यूरोप के लिए ऊर्जा प्रवेश द्वार के रूप में उसकी रणनीतिक भूमिका के साथ पूरी तरह मेल खाती है। भारत की अगुवाई वाली प्रमुख पहलों—अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस में हमारा सहयोग भी महत्वपूर्ण है।

भारत और इटली दोनों वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों—इंडो-पैसिफिक और भूमध्यसागर के केंद्र में स्थित हैं। दरअसल, हम एक नए ह्यइंडो-मैडिटेरेनियनह्न क्षेत्र के उभरने को देख रहे हैं, जो व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, डेटा और विचारों का एक महत्वपूर्ण गलियारा बन रहा है और हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ता है। यह ऐसी साझेदारी है, जो दो महाद्वीपों को जोड़ती है। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा एक ऐसी दूरदर्शी योजना है, जिसका उद्देश्य आधुनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा प्रणालियों व मजबूत सप्लाई चेन के माध्यम से हमारे क्षेत्रों को जोड़ना है।

हम अपनी साझा चुनौतियों का समाधान दोनों देशों के गहरे संबंधों और लंबे सांस्कृतिक जुड़ाव के आधार पर कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में ह्यधर्मह्न का विचार उस जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है, जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करता है। वहीं ह्यवसुधैव कुटुंबकम ?ह्न का सिद्धांत डिजिटल युग में और अधिक प्रासंगिक है।

ये मूल्य इटली की मानवतावादी परंपरा से भी मेल खाते हैं, जिसकी जड़ें पुनर्जागरण काल में हैं। यह परंपरा हर व्यक्ति की गरिमा और संस्कृति की उस शक्ति पर जोर देती है, जो समाजों और लोगों को एकजुट कर सकती है। इसलिए हमारी साझा दृष्टि का उद्देश्य लोगों को केंद्र में रखते हुए इस साझेदारी को मजबूत, आधुनिक और भविष्य उन्मुख आधार प्रदान करना है।

मुश्किल से मिलता है देशभक्त बनने का सुलभ अवसर

श्रीराम

देशभक्त बनने के और भी अनेक अवसर हैं। आप पेट्रोल-डीजल कम खर्च करें तो देशभक्त। बल्कि तेल कम खाने पर भी देशभक्त हो सकते हैं। देशभक्ति ऐसी सुलभ कब थी जी! देशभक्त बनने का ऐसा सुलभ अवसर कब-कब मिलता है जी। सो मौका है देशभक्त बन लो! अभी तक देशद्रोही बनने के अवसर ही ज्यादा मिलते रहे हैं। किसान फसल के भाव मांगे, तो देशद्रोही, मजदूर मजदूरी बढ़ाने की मांग करें, तो देशद्रोही, युवा रोजगार मांगें तो देशद्रोही और छात्र आंदोलन करें तो देशद्रोही। लग रहा था जैसे देशद्रोह के काम ही ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अब देशभक्ति के काम करने के अवसर भी खूब हैं। एक साल तक सोना मत खरीदो-देशभक्ति है।

हालांकि, सोना इतना महंगा है-कौन खरीदता है जी! लेकिन अपने यहां धनतेरस पर तो चाहे सोना न खरीदो, पर शादी-ब्याह में सोने की खरीददारी मजबूरी मानी ही जाती है। शादी-ब्याह में बहू-बेटी को सोने के गहने उपहार में देना बेशक शान होती होगी, शुभ भी होता होगा। लेकिन देशभक्ति न पहले थी, न अब होगी। अलबत्ता सोने के गहने उपहार में न देने पर यह चर्चा जरूर हो जाती थी कि देखो बिना दान-दहेज के शादी हुई है। न कोई गहना न तिलक। कई लोग इसे लुक्खी शादी मानते थे। कई लोग इसे खोट छुपाने का आवरण भी मानते थे। लेकिन दिखावे के लिए कहा जाता था कि देखो कितनी आदर्श शादी है। लेकिन ऐसी शादी अब देशभक्तिपूर्ण शादी भी मानी जाएगी। छाती ठोककर।

इसी तरह विदेश यात्रा है जी। अब वैसे तो विदेश यात्रा कौन करता है जी! लेकिन नेता, अफसर, फिल्म वाले, बिजनेस वाले और दौलतमंद तो विदेश यात्रा करते ही हैं। हां, बेहतर शिक्षा पाने के लिए छात्र भी विदेश यात्रा करते हैं और बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले युवा भी विदेश यात्रा करते हैं। वे कभी कंटेनरों में भर कर विदेश जाते हैं, कभी कबूतरबाजी के जरिए जाते हैं, तो कभी डंकी रूट से जाते हैं। अब नेताओं-अफसरों की विदेश यात्राओं को तो चाहे कितना ही देशभक्तिपूर्ण माना जाता हो, लेकिन कंटेनरों में जाने वालों ओर डंकी रूटवालों की विदेश यात्रा को कभी देशभक्तिपूर्ण नहीं माना जाता।

लेकिन जो विदेश यात्रा को तरस जाते हैं, तड़प जाते हैं, किलसते रहते हैं। उनकी इस किलस को अब देशभक्ति माना जाएगा। बल्कि अब तो समस्या यह आने वाली है कि बात-बात पर लोगों को पाकिस्तान जाने की सलाह देने वाले कहीं लोगों को जबर्दस्ती पाकिस्तान न भेजने लगे ताकि उन पर देशद्रोही होने का पक्का ठप्पा लगाया जा सके। खैर, साल भर तक सोना न खरीदने, विदेश न जाने के अलावा और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा की तर्ज पर देशभक्त बनने के और भी अनेक अवसर है। जैसे आप पेट्रोल-डीजल कम खर्च करके देशभक्त हो सकते हैं, बल्कि तेल कम खाने पर भी देशभक्त हो सकते हैं। देशभक्ति ऐसी सुलभ कब थी जी!

गोडलवाही पहुंचा जिला प्रशासन, 15 पंचायतों के ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान

हितग्राहियों को बांटे आवास, राशन कार्ड, पेंशन और गैस कनेक्शन, मेधावी छात्र भी सम्मानित

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

सुशासन तिहार के तहत जिला प्रशासन की टीम बुधवार को छुरिया विकासखंड के अंतिम छोर पर बसे वनांचल ग्राम गोडलवाही पहुंची। यहां 15 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों के लिए जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर मौके पर ही आवेदन लिए और समस्याओं का निराकरण किया।

इन योजनाओं का मिला लाभ

शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 हितग्राहियों को पूर्णता प्रमाण पत्र दिए गए। 15 लोगों को नए राशन कार्ड, 11 को जॉब कार्ड, 10 को पेंशन स्वीकृति और 5 हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए। 13 लोगों को आयुष्मान कार्ड और 2 बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 20 हितग्राहियों को शौचालय निर्माण की स्वीकृति और 11 स्वच्छता दीदियों को किट दी गई। कृषि विभाग ने 4 हितग्राहियों को मूंग बीज बांटा। बिहान योजना में महिला समूह को 6 लाख रुपए का ऋण दिया गया। मत्स्य विभाग ने मछुआ समिति को जाल और आईस बॉक्स दिए। मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कर सुपोषण किट बांटी।

शासन खुद पहुंच रहा गांव-गांव

जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुसार सुशासन तिहार के जरिए शासन-प्रशासन खुद गांव-गांव जाकर समस्याओं का समाधान कर रहा है। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

संवाद से समाधान का माध्यम

जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने कहा कि सुशासन तिहार संवाद से समाधान का प्रभावी माध्यम है। ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। उन्होंने जल संरक्षण और जैविक खेती अपनाने की अपील की।

62 स्थानों पर लग रहे शिविर

अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय ने बताया कि जिले में 62 स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। जिन आवेदनों का तत्काल निराकरण संभव है उनका मौके पर समाधान किया जा रहा है। शेष आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण कर जानकारी दी जाएगी। राजस्व संबंधी प्रकरणों का प्राथमिकता से समाधान हो रहा है।

शिविर में गोडलवाही, अरजकुंड, बडगांव, बरबसपुर, गिदरी, गुण्डरदेही, उमरवाही, कलडबरी, कांपा, करमरी, महरूम, मासुलकसा, परेवाडीह, रानामटिया और रतनभाट पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान उपाध्यक्ष जनपद पंचायत प्रशांत ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य गोपाल सिंह भुआर्य, डिप्टी कलेक्टर विश्वास कुमार, तहसीलदार विजय कोठारी सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

खास खबर

खैरागढ़ आरसेटी में ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण बैच का समापन, प्रमाण पत्र वितरित

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

कलेक्टर बोले : कौशल विकास से महिलाएं बनें आत्मनिर्भर, स्वरोजगार अपनाकर बनें प्रेरणा

भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी खैरागढ़ में देवारीभाट स्थित डीपीआरसी भवन में संचालित ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण बैच का समापन समारोह गरिमामय वातावरण में हुआ। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चन्द्रवाल, जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल और आरसेटी निदेशक सी. एस. ठाकुर ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

कौशल से बनें आर्थिक रूप से मजबूत

कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने कहा कि कौशल विकास और स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है। महिलाएं अपने कौशल और आत्मविश्वास से आर्थिक रूप से मजबूत बनकर परिवार व समाज के विकास में अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से स्वरोजगार अपनाकर जिले की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनने का आह्वान किया।

कम लागत में बेहतर आय का माध्यम

जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल ने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है। ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय कम लागत में बेहतर आय दे सकते हैं। आरसेटी निदेशक सी. एस. ठाकुर ने मुद्रा ऋण योजना, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय अनुशासन की जानकारी दी।

प्रशिक्षणार्थियों ने साझा किए अनुभव

प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि उन्हें ब्यूटी पार्लर व्यवसाय से जुड़ा तकनीकी ज्ञान, ग्राहक व्यवहार, आधुनिक सौंदर्य सेवाएं, स्वच्छता प्रबंधन और व्यवसाय संचालन की जानकारी मिली। प्रशिक्षण का संचालन संकाय सदस्य ओम मिश्रा और अभिषेक तिवारी ने किया। आयोजन में कार्यालय सहायक संतोष कुमार करकी का विशेष सहयोग रहा।

नगरपालिका निर्वाचन 2026 : व्यय प्रेक्षक के लिए राकेश हेड़ाउ लायजन अधिकारी नियुक्त

राजनांदगांव। नगरपालिकाओं के आम और उप निर्वाचन 2026 के लिए जिले में व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। संचालनालय कोष एवं लेखा के संयुक्त संचालक (वित्त) प्रेमलाल साहरा को जिले का व्यय प्रेक्षक नामनिर्दिष्ट किया गया है।

व्यवस्था व समन्वय के लिए अधिकारी तय

व्यय प्रेक्षक की व्यवस्था और समन्वय के लिए सहायक कोषालय अधिकारी (वित्त) जिला कोषालय राजनांदगांव और प्रभारी उप कोषालय अधिकारी डोंगरगढ़ राकेश कुमार हेड़ाउ को लायजन अधिकारी नियुक्त किया गया है। व्यय प्रेक्षक प्रेमलाल साहरा का मोबाइल नंबर 7470363030 और लायजन अधिकारी राकेश कुमार हेड़ाउ का मोबाइल नंबर 7898961104 है।

चेम्बर ऑफ कॉमर्स के महाअधिवेशन में वित्त मंत्री बोले : देश बनेगा 36 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

राजनांदगांव को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल करना एक बड़ी उपलब्धि : डॉक्टर रमन सिंह

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज राजनांदगांव का जिला स्तरीय व्यापारी महाअधिवेशन हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए।

स्टेट कैपिटल रीजन से जुड़ेगा राजनांदगांव

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा स्टेट कैपिटल रीजन में राजनांदगांव जिले को शामिल करना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे शहरों को एकीकृत कर समेकित और योजनाबद्ध विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान में 4 ट्रिलियन डॉलर है जो आने वाले वर्षों में 36 ट्रिलियन डॉलर की बनेगी। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि हाईड्रोजन एनर्जी, बायोफ्यूल, एआई जैसे नए क्षेत्रों में व्यापार के अच्छे अवसर हैं। नये उभरते अवसरों की तलाश कर फायदा लें।

जीएसटी और औद्योगिक नीति पर चर्चा

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी लागू होने से 17 प्रकार के कर और 13 प्रकार के अन्य कर समाप्त हुए। एक देश एक कर की व्यवस्था से मूल्यों में कमी आई। उन्होंने कहा कि फर्जी बिल लगाकर इनपुट क्रेडिट घोटाला करने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। व्यापारी वर्ग शासन की औद्योगिक नीति का अध्ययन करें। 200 करोड़ रुपए की रुकी औद्योगिक सब्सिडी के लिए 468 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया गया।

उन्होंने बताया कि जॉब पार्क की शुरुआत की गई है जिसमें उद्योगों पर आधारित रोजगार मिलेंगे। रजिस्ट्री के क्षेत्र में नवाचार से राजस्व बढ़ा है। स्टेट कैपिटल रीजन से जुड़ने के बाद राजनांदगांव सफलता के नए आयाम प्राप्त करेगा।

इस अवसर पर नंदलाल राठी, टीकम दास साहू, हीना बेन रायचा, शेखर बोथरा, उन्नति पंजवानी और गुरबचन कौर सावलानी को व्यापारी-उद्यमी सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थोरानी, समाजसेवी खूबचंद पारख, ज्ञानचंद बाफना, अरूण डुलानी, कोमल सिंह राजपूत, जितेन्द्र मुदलियार, बलदेव सिंह भाटिया, पद्मश्री फूलबासन यादव सहित चेम्बर के सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर आतंकवाद के खिलाफ ली शपथ

विधायक बोलीं : पंचायती राज को मजबूत कर गांव-गांव तक पहुंचाया लोकतंत्र

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर गुरुवार को शहर कांग्रेस कमेटी ने विधायक निवास में श्रद्धांजलि सभा और आतंकवाद विरोध दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और शांति बनाए रखने की शपथ ली गई।

आधुनिक भारत के अग्रदूत थे राजीव गांधी

विधायक यशोदा नीलाम्बर वर्मा ने कहा कि राजीव गांधी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छुईं। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर उन्होंने लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाया। उनका बलिदान देश की एकता के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके खिलाफ हर वर्ग को एकजुट होना होगा।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरुण भारद्वाज ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माण के अग्रदूत थे। उन्होंने तकनीक, संचार, शिक्षा और पंचायती राज के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने का ऐतिहासिक काम किया।

ये रहे मौजूद

कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस सदस्य निलांबर वर्मा, शहर अध्यक्ष अरुण भारद्वाज, नेता प्रतिपक्ष दीपक देवांगन, ग्रामीण अध्यक्ष संदीप सिरमौर, उपाध्यक्ष पूरन सारथी, रविन्द्र सिंह गहरवार, भरत चंद्राकर, महामंत्री यतेन्द्र जीत सिंह छोटू, नरेन्द्र सेन, गैंदालाल खुले, महेश साहू, कन्हैया रजक, रतन सिंघी, भगत वर्मा, दामन वर्मा, जवाहर सिंह बैस सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में कांग्रेसजनों ने राजीव गांधी के आदर्शों पर चलने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया।

खैरागढ़ में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर संपन्न, 146 खिलाड़ियों ने लिया प्रशिक्षण

5 केंद्रों पर 1 से 20 मई तक चला शिविर, खिलाड़ियों को बांटे प्रमाण पत्र

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से जिला मुख्यालय के राजा फतेह सिंह खेल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। 1 से 20 मई तक चले इस शिविर में जिले के 146 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

पांच केंद्रों पर दिया गया प्रशिक्षण

शिविर राजा फतेह सिंह खेल मैदान खैरागढ़, केकती बाड़ी मैदान छुईखदान, खेल मैदान अकरजन, सजेस साल्हेवारा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला मैदान गण्डई में आयोजित हुआ। अनुभवी प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास, खेल तकनीक और फिटनेस का प्रशिक्षण दिया।

शिविर में फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, साइक्लिंग, फेंसिंग, जूडो और एथलेटिक्स का अभ्यास कराया गया। खिलाड़ियों को खेल कौशल के साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और शारीरिक दक्षता का महत्व भी बताया गया।

14 प्रशिक्षकों ने दिया प्रशिक्षण

नीलू सिंह, शितांषु गुप्ता, प्रिनकेश कश्यप, आशीष पटेल, ताजु खान, गौरी, नंदेश्वरी जोशी, कांति चंद्राकर, जनक साहू, कुशल सिंह ध्रुव, रोहित अचला, निधि साहू, रोशनी रावटे और रूपेंद्र साहू ने प्रशिक्षक के रूप में खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सिखाईं।

समापन में बांटे प्रमाण पत्र

समापन समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष गिरजा चंद्राकर, सांसद प्रतिनिधि भगवत शरण सिंह, विकेश गुप्ता, पार्षद सुमित टंडिया, रूपेंद्र रजक, सूरज देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र दिए और नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं।

मानव मंदिर में बासी मिठाई बेचने का आरोप, महिला के हंगामे के बाद फूड विभाग ने लिए सैंपल

संचालक पर दुर्व्यवहार का आरोप, खाद्य सुरक्षा टीम ने की जांच शुरू

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

शहर के चर्चित मिठाई संस्थान मानव मंदिर में बासी मिठाई बेचने और शिकायत करने पर महिला से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। राज फैमली वार्ड निवासी प्रकृति सिंह उर्फ शैवी ने फूड विभाग में लिखित शिकायत की है। शिकायत के बाद फूड सेफ्टी यूनिट ने मौके पर पहुंचकर मिठाई के सैंपल जब्त किए और पंचनामा बनाया।

प्रकृति सिंह के मुताबिक उन्होंने मंगलवार रात मानव मंदिर से आम और दूध से बनी करीब 150 रुपए की मिठाई खरीदी थी। घर पहुंचकर डिब्बा खोला तो उसमें से तेज गंदी बदबू आ रही थी। उन्होंने मिठाई फ्रिज में रख दी और बुधवार सुबह शिकायत लेकर दुकान पहुंचीं।

दुर्व्यवहार का आरोप

महिला का आरोप है कि होटल प्रबंधन ने शिकायत सुनने के बजाय उन्हें ही गलत ठहराया और दुर्व्यवहार किया। इसके बाद दुकान परिसर में हंगामा हो गया। प्रकृति सिंह ने कहा कि संचालक ने ह्यजो करना है कर लो की धमकी भी दी।

फूड विभाग ने शुरू की जांच

मामले की जानकारी मिलते ही खैरागढ़ की फूड सेफ्टी यूनिट मानव मंदिर पहुंची। टीम ने शिकायतकर्ता की मिठाई और दुकान में रखे संबंधित खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। लैब रिपोर्ट का इंतजार है।

प्रकृति सिंह ने बताया कि वे छोटे बच्चे को स्तनपान कराती हैं। खराब मिठाई खाने से उनके साथ बच्चे की सेहत भी खराब हो सकती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रतिष्ठित संस्थानों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर निगरानी कौन रख रहा है।

खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार दूध और आम से बनी मिठाइयों में तापमान और स्टोरेज में लापरवाही से बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। इससे फूड पॉइजनिंग और संक्रमण का खतरा रहता है। फिलहाल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

राजनांदगांव: 86 पौवा अवैध शराब के साथ आदतन आरोपी गिरफ्तार

राजनांदगांव। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आदतन आरोपी कृष्णा रजक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 86 पौवा गोवा शराब मात्रा 12.040 बल्क लीटर कीमत 12340 रुपए जब्त की गई। आरोपी को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेण्डर किरो के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में पुलिस ने 20 मई को मुखबिर की सूचना पर कैलाश नगर पावर हाउस निवासी कृष्णा रजक के पास से अवैध रूप से बिक्री के लिए रखी शराब बरामद की।

आदतन अपराधी है आरोपी : 27 वर्षीय कृष्णा रजक कोतवाली थाने का सूचीबद्ध गुंडा बदमाश है। इसके खिलाफ पहले से मारपीट, अवैध शराब बिक्री और आर्म्स एक्ट के 15 मामले दर्ज हैं। इनमें 2019 से 2024 के बीच धारा 294, 323, 506, 325, 34 भादवि, 34(1) आबकारी एक्ट, 25, 27 आर्म्स एक्ट और जुआ एक्ट के तहत कई अपराध पंजीबद्ध हैं।

कार्रवाई जारी रहेगी : पुलिस ने कहा कि असामाजिक तत्वों और अवैध शराब बिक्री में लिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार शाह, साइबर प्रभारी विनय पामर, सउनि इसराफिल खान, प्रधान आरक्षक संदीप चौहान, आरक्षक अविरल भगत, अश्वनी ठाकुर और महिला आरक्षक वर्षा ध्रुव की अहम भूमिका रही।

पीपीएचटी प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 538 परीक्षार्थी हुए शामिल

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

जिले में बुधवार को व्यापम द्वारा आयोजित पीपीएचटी (Pre Pharmacy Test) प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हुई। परीक्षा के लिए जिले में 3 केंद्र बनाए गए थे।

745 में से 538 ने दी परीक्षा

परीक्षा के लिए कुल 745 परीक्षार्थियों का पंजीयन था। इनमें से 538 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 207 अनुपस्थित रहे। व्यापम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी केंद्रों पर प्रवेश, दस्तावेज सत्यापन, बैठने और सुरक्षा की व्यवस्था की गई।

समय पर बंद हुए गेट

निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया गया। पर्यवेक्षक दल और एफएसटी टीम ने परीक्षा के दौरान लगातार निगरानी रखी। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के समन्वित प्रयास से परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित माहौल में पूरी हुई।

फिल्म 'डीसी' से निर्देशक लोकेश कनगराज कर रहे हैं एक्टिंग डेब्यू

वामिका गब्बी मौजूदा वक्त में इंडस्ट्री की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में से एक हैं। पिछले महीने 'भूत बंगला' की सफलता के बाद कल ही उनकी नई फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' रिलीज हुई है। अब उनकी आगामी फिल्म 'डीसी' रिलीज को तैयार है। फिल्म का ट्रेलर 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में जारी किया गया है। 'डीसी' से निर्देशक से एक्टर बने लोकेश कनगराज अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं।

3 मिनट 13 सेकंड के इस ट्रेलर में लोकेश कनगराज को देवदास और वामिका को चंद्रा के रूप में दिखाया गया है। ट्रेलर में दिखाया जाता है कि चंद्रा के माता-पिता ने कोलकाता में उसे कई साल पहले अवैध रूप से देह व्यापार में बेच दिया था। अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। जल्द ही पता चलता है कि देवदास एक पुलिस वाले और डॉक्टर चंद्रा की हत्या के आरोप में वॉन्टेड है। इसके बाद ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, खूनखराबा, बम धमाके और गोलीबारी देखने को मिलती है। ट्रेलर में लोकेश के साथ-साथ वामिका भी कई मौकों पर एक्शन करती नजर आती हैं। ट्रेलर का अंत एक रोमांटिक अंदाज में होता है, जहां वामिका और लोकेश सूर्यास्त के समय एक पहाड़ी पर खड़े नजर आते हैं। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर भी चर्चा में आ गया। हालांकि, अधिकांश यूजर्स ट्रेलर में सबसे ज्यादा प्रभावित अनिरुद्ध के म्यूजिक से हुए हैं। जबकि कई यूजर्स ने ट्रेलर में वामिका और लोकेश की भी जमकर तारीफ की है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, ट्रेलर जारी होने के बावजूद अभी तक फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है।

फिल्में सिर्फ समाज सुधार के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए भी बनती हैं

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग फिल्म 'सिस्टम' रिलीज के लिए तैयार है। इस बीच प्रमोशन में व्यस्त सोनाक्षी ने सिनेमा के उद्देश्य पर बात की। अपनी स्पष्ट राय रखते हुए उन्होंने बताया कि फिल्मों का एकमात्र मकसद समाज में बदलाव लाना नहीं है। फिल्में सिर्फ समाज सुधारने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए भी बनती हैं। अभिनेत्री का मानना है कि फिल्में मुख्य रूप से मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं और नैतिक शिक्षा देना फिल्म मेकर्स का काम नहीं है। खास बातचीत में सोनाक्षी ने कहा, 'मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि फिल्मों को सिर्फ समाज को सही रास्ते पर लाने का जरिया माना जाए। फिल्में मनोरंजन के लिए भी बनाई जाती हैं। सही और गलत की शिक्षा हमें अपने माता-पिता और स्कूल से मिलनी चाहिए। यह एक्टर्स या फिल्म मेकर्स काम नहीं है।' सोनाक्षी ने बताया, 'आज हम एक वकील की कहानी बनाएंगे, कल हम एक सीरियल किलर की कहानी बना सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि लोग जाकर दूसरों को मारना शुरू कर दें। नैतिक मूल्य और सिद्धांत घर पर सिखाए जाते हैं। यह सिखाना हमारा काम नहीं है।' अभिनेत्री ने स्पष्ट किया कि फिल्मों में 12, 16 या 18 साल के दर्शकों के लिए उम्र के हिसाब से रेटिंग्स होती हैं। दर्शक खुद सही और गलत के बीच फर्क समझने में सक्षम हैं। सोनाक्षी ने बताया, 'कई बार फिल्मों को लेकर बड़ी बहस छिड़ जाती है कि यह गलत है, इसे दिखाना नहीं चाहिए। माफ कीजिए, लेकिन फिल्म एक कहानी है। दर्शकों को फिल्म को मनोरंजन के तौर पर देखना चाहिए। आखिरकार यह सिर्फ एक कहानी होती है।' उन्होंने यह भी कहा कि कला समाज का आईना होती है। फिल्में अक्सर असल जिंदगी की घटनाओं या सच्ची कहानियों पर आधारित होती हैं। अगर कोई फिल्म 'सिस्टम' की तरह दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दे तो यह अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर फिल्म समाज सुधारने की जिम्मेदारी ले। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'सिस्टम' 22 मई को प्राइम वीडियो पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म का निर्माण पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा और स्मिता बालिगा ने किया है। अश्विनी अय्यर की फिल्म में सोनाक्षी के साथ अभिनेत्री ज्योतिका भी नजर आएंगी।

अपने पिता कमल हासन की हॉलीवुड फिल्म के लिए यह खास काम करेंगी श्रुति

अभिनेता और राजनेता कमल हासन तमिलनाडु चुनावों के बाद अब वापस फिल्मों में व्यस्त होने जा रहे हैं। चर्चा है कि वे पहली बार एक हॉलीवुड फिल्म में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। उनकी बेटी श्रुति हासन इस फिल्म के लिए एक खास काम करेंगी। एक खबर के अनुसार, कमल हासन एक हॉलीवुड फिल्म में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म की कहानी कमल की बेटी श्रुति हासन लिख रही हैं। हालांकि, अभी तक दोनों की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हाल ही में उनकी अमेरिका यात्रा को स्टंट डायरेक्टर जोड़ी 'अंबरीव' के साथ आने वाली फिल्म से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि यह यात्रा उनकी हॉलीवुड फिल्म के सिलसिले में थी। कमल हासन इस समय कई बड़ी फिल्मों से जुड़े हुए हैं। कमल लगभग 40 साल बाद रजनीकांत के साथ निर्देशक नेल्सन की फिल्म में नजर आएंगे। साथ ही वह रजनीकांत की फिल्म 'थलाइवर 173' को भी सपोर्ट कर रहे हैं।

इंजीनियरिंग से अभिनय की दुनिया में रखा कदम, 'मसान' से 'छावा' तक शानदार सफर

मुंबई के चेंबूर में जन्मे विक्की कौशल आज हिंदी सिनेमा के सबसे सशक्त और संवेदनशील अभिनेताओं में शुमार हैं। इंजीनियरिंग छोड़कर अभिनय की राह चुनने वाले इस साधारण पंजाबी लड़के ने 'मसान', 'उरी', 'सरदार उधम' और 'छावा' जैसी फिल्मों से न केवल अपने अभिनय का लोहा मनवाया, बल्कि मेहनत और सच्चाई की मिसाल भी पेश की। विक्की के पिता, शाम कौशल, बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर हैं। घर में सिनेमा का माहौल था, लेकिन विक्की को शुरुआत में अभिनय का शौक नहीं था। उन्होंने रामनारायण रुइया कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों में, वह थिएटर से जुड़े और धीरे-धीरे अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 2015 में, फिल्म 'मसान' से, उन्होंने बड़े पर्दे पर डेब्यू किया। फिल्म में उनकी 'दीपक' वाली भूमिका को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और एक झटके में विक्की कौशल इंडस्ट्री का नया चेहरा बन गए। उसके बाद विक्की ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2019 में 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया।

पेरेंटिंग पर बोलीं शेफाली शाह

अभिनेत्री शेफाली शाह ने बच्चों की परवरिश को लेकर अपना नजरिया पेश किया है। खासकर ऐसी दुनिया में, जहां अल्फा मेल कल्चर और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को लेकर जोरदार बहसें चल रही हैं। शेफाली ने बताया कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को परवरिश का एक बेहद सीधा-सादा नियम सिखाया है और उनका मानना है कि अच्छी परवरिश के नतीजे सामने आने से बहुत पहले ही इसकी शुरुआत हो जाती है। उन्होंने क्या कहा? जानिए अल्फा मेल और ट्रेडिशनल पत्नी वाली सोच से कैसे निपटा जाए?

शेफाली शाह ने मां बनने और बेटों की परवरिश के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने लिली सिंह के पॉडकास्ट पर इस बारे में बेझिझक अपनी बात रखी। एक्ट्रेस से जब पूछा गया कि दो बेटों की परवरिश करते समय 'अल्फा मेल' और 'पारंपरिक पत्नी' वाली सोच से कैसे निपटा जाए? इस पर अभिनेत्री ने कहा, 'हमारी बेटियां तभी सुरक्षित रहेंगी, जब हमारे बेटों की परवरिश सही तरीके से होगी। मैंने एक ऐसी बात सोची जो मैंने उन्हें बताई और मुझे लगता है कि यह बात हर किसी पर लागू होती है। आप दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करें, जैसा आप खुद अपने साथ होने की उम्मीद करते हैं। यह सच में आसान है। इसमें न कुछ ज्यादा है और न ही कुछ कम'। बोलीं- 'जब वे 30 के होंगे तभी मालूम होगा कि...' शेफाली शाह ने आगे कहा, 'बाकी सब... बहुत शोर-शराबा है। क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा बर्ताव हो? नहीं? तो किसी दूसरे इंसान के साथ भी ऐसा मत कीजिए'। शेफाली शाह ने माता-पिता के कंट्रोल की सीमाओं और बच्चों की परवरिश में आने वाली अनिश्चितता के बारे में भी बात की, क्योंकि बड़े होकर बच्चे आखिरकार अपनी खुद की सोच बनाते हैं। उन्होंने कहा, 'क्या मैं कामयाब हुई? यह मुझे तभी पता चलेगा जब वे 30 साल के हो जाएंगे'। 'मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगी' शेफाली ने अपने दोनों बेटों को लेकर कहा, 'वे बड़े हो रहे हैं। उनके अपने विचार होंगे। वे हर उस बात को गलत साबित करना चाहेंगे, जो कोई बड़ा, कोई माता-पिता या कोई मां कहती है। अगर वे बुरा बर्ताव करते हैं, तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। मैं नहीं ले सकती। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उस इंसान का अपना दिमाग है। मैंने जितना हो सका, उतना अच्छा किया। मुझे लगता है कि वे काफी हद तक ठीक ही बने हैं'। बता दें कि शेफाली शाह की शादी फिल्ममेकर विपुल अमृतलाल शाह से हुई है। कपल के दो बेटे हैं- आर्यमन और मौर्य।

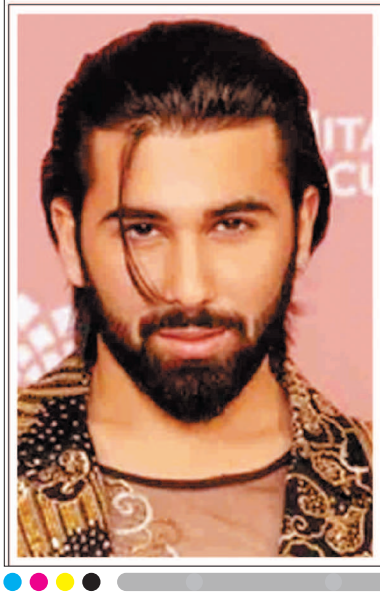

मेरा पंगा सारा खान से नहीं, अमृता सिंह से है और मैं नेपो किड नहीं हूं

कभी बॉलिवुड सिलेब्स के साथ फोटो खिंचवाकर चर्चा में आए ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी आज खुद एक सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं। वहीं, अब जल्द ही वह टीवी के मशहूर रिएलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के 15वें सीजन में खतरों से खेलते हुए भी दिखेंगे। ऐसे में, जब हमने ओरी से इस शो में भागीदारी की वजह जाननी चाही तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। ओरी का कहना है कि बहुत समय से उन्हें खुशी, दुख, दर्द, भय कोई भी इमोशन महसूस नहीं होता, इसलिए उन्होंने इस शो को हां कहा ताकि वे शो के चुनौतीपूर्ण टास्क के दौरान वापस जिंदा महसूस कर सकें।

काफी समय से बहुत डिप्रेशन में हूं

बकौल ओरी, 'मैं जिस तरह की जिंदगी जीता हूं, उसमें मैं हर तरह से अहसास के प्रति डीसेंसिटाइज यानी संवेदनहीन हो चुका हूं। मैं चाहे नई गाड़ी ले लूं, बैग ले लूं, हॉलिडे पर चला जाऊं, मुझे कोई भी चीज एक्साइट नहीं करती। मैंने खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए इसलिए हां कहा, क्योंकि मैं जिंदगी को महसूस करना चाहता हूं। मैं फिर जिंदा महसूस करना चाहता हूं। मैं काफी समय से बहुत ही डिप्रेस्ड (अवसादग्रस्त) रहा हूं। मुझे बहुत अजीब लगता है, जब मैं बाहर जाता हूं और मेरे इतने सारे फैंस मुझे सिर्फ देखकर इतने उत्साहित होते हैं। मतलब मेरे जैसे खुद अवसाद में जी रहे इंसान के लिए यह विडंबना ही है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो ओरी बहुत खुशमिजाज लगते हैं? इस पर वह कहते हैं, 'आपको दुनिया के सामने अपना बेस्ड साइड ही दिखाना पड़ता है। आप वहां ऐसी पिक्चर्स नहीं पोस्ट कर सकते जिसमें खुश न हों पर मैंने बहुत समय से कुछ महसूस नहीं किया है।'

खुशी, दुख, उत्साह कुछ महसूस नहीं होता

क्या ओरी को जिंदगी में किसी चीज से डर लगता है? यह पूछने पर वह कहते हैं, 'नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे याद नहीं आता कि आखिरी बार कब मैंने कोई भी फीलिंग महसूस किया था। खुशी, गुस्सा, दुख, उत्साह, कोई भी अहसास। कई बार मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मुझे कुछ महसूस करना है। इसके लिए मुझे खुद पर बहुत जोर डालना पड़ता है।

सांस भी लेता हूं तो लोग जज करते हैं

ओरी को सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी और ट्रोलिंग दोनों भरपूर मिली है। उन्हें काफी जज भी किया जाता है। वह कहते हैं, 'मुझे दोनों ही चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई नेपो किड नहीं हूं। मैं फेमस पैदा नहीं हुआ हूं। मैंने अपनी प्रसिद्धि कमाई है तो अगर मैं पहले इसके बिना रहा हूं तो बाद में भी रह सकता हूं। रही बात जजमेंट की तो लोगों ने मुझे हर वक्त जज किया है, इसलिए मैं उसके प्रति भी पूरी तरह डीसेंसिटाइज हो चुका हूं। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं कुछ भी करूं लोग मुझे जज ही करते हैं। मैं घर से बाहर निकलता हूं और जज होता हूं।

मेरा पंगा सारा नहीं, उनकी मां से है

पिछले दिनों ओरी का उनकी खास दोस्त सारा अली खान के साथ विवाद भी सुर्खियों में रहा। इस बारे में ओरी बताते हैं, 'मेरा सारा के साथ कोई विवाद नहीं है। मेरा विवाद उसकी मां अमृता सिंह के साथ है, मगर मैं सारा के साथ दोस्त होने का दिखावा नहीं कर सकता, जबकि उसकी मां ने मेरे साथ इतना गलत किया। मैंने यही कहा है कि जो अमृता ने मेरे साथ किया, वो ठीक नहीं था और जब तक वो माफी नहीं मांगती, मैं सारा अली खान के साथ दोस्ती का दिखावा नहीं कर सकता। वरना सारा के साथ मेरी कोई बैर नहीं थी। उन्होंने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी है। मैं अब भी इंतजार कर रहा हूं।'

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने दी विकास कार्यों की बड़ी सौगात, सड़क पुल-पुलिया निर्माण का किया भूमिपूजन

भगवतीटोला से भैंसबोड तक बनेगी 2 .40 किमी पक्की सड़क, चिर परिचित अंदाज में उप मुख्यमंत्री ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठे, समस्याएं सुनी, अनेक विकास कार्यों की घोषणा की

नई दृष्टिबिंदु / कबीरधाम

कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम भगवतीटोला से भैंसबोर्ड मार्ग पर अब सफर आसान और तेज होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम बबई में विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। उन्होंने यहां 4.36 करोड़ रूपए से अधिक की लागत बनने वाले 2.40 किमी सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों का वर्षों पुराना इंतजार खत्म किया। यह सड़क मार्ग क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ ग्रामीणों के आवागमन को आसान और सुगम बनाएगा। इस दौरान साजा विधायक ईश्वर साहू, नितेश अग्रवाल, लाला राम साहू, भुखन साहू, परदेशी पटेल, जलेश्वर वर्मा, लेख चंद पटेल सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित रहे।

इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने चिर परिचित अंदाज में जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से आत्मीय चर्चा की, उनकी समस्याएं सुनीं और कई मांगों पर तत्काल विकास कार्यों की घोषणा कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने महामाया मंदिर में कक्ष निर्माण के लिए 2 लाख, भगवता टोला में सामुदायिक भवन के लिए 6.5 लाख, सामुदायिक शौचालय निर्माण, समतलीकरण के लिए 2.5 लाख, बबई में मुरमीकरण

के लिए 2 लाख रुपए, भैंसबोड में रंग मंच के लिए 4 लाख, पचरी निर्माण के लिए 3 लाख, ग्राम नरोधी में मुरमीकरण के लिए 4 लाख, सिंगारपुर में सामुदायिक भवन के लिए 6.5 लाख, ग्राम धनगांव में मुख्यमंत्री ग्रामसड़क योजना के तहत पक्की सड़क, मरार समाज के सामुदायिक भवन कक्ष के लिए 5 लाख और महिला स्व सहायता समूह द्वारा मांग पर सोलर आटा चक्की बनाने की घोषणा की।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गांवों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क, आवास, किसान हित और महिला सशक्तिकरण से जुड़े काम तेजी से किए जा रहे हैं, जिससे गांवों की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1 हजार रुपए की राशि दी जा रही है, जिससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल रही है। साथ ही सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों की स्वीकृति देकर बड़ा फैसला लिया गया, ताकि जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिल सके। महतारी वंदन से अब तक 27 किस्तों के माध्यम से हर हितग्राही माता बहनों के खाते में 27 हजार की राशि पहुंच चुकी है। इस दौरान उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में सड़क व अन्य निर्माण पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

साजा विधायक ईश्वर साहू ने कहा कि आज 4 करोड़ 36 लाख रुपए के लागत के विकास कार्यों के भूमिपूजन की सभी को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ सरकार पूरा कर रही है। सरकार समर्थन मूल्य में धान की खरीदी कर रही है। महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले जा रहे है। किसानों को बोनस राशि का भुगतान एक मुश्त किया गया है। मोदी जी के सभी वादे को पूरा किया गया है। प्रदेश के सभी जिले में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है जहाँ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पहुंच रहे है और वहां का निरीक्षण कर रहे है साथ ही अनेक विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे है।

खास खबर

समीक्षा बैठक : लंबित ऋण प्रकरणों का शीघ्र करें निराकरण -कलेक्टर तलिका प्रजापति

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न बैंकिंग, वित्तीय समावेशन एवं स्वरोजगार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, लीड बैंक प्रबंधक, जिले के सभी बैंकर्स, तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने नवीन बैंक शाखाओं के शुभारंभ, बैंक विहीन गांवों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा ऋण वितरण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल ट्रांजेक्शन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री खाद्यान्न उन्नयन योजना, पीएमएफएमई योजना, स्वयं सहायता समूहों को केसीसी ऋण वितरण एवं पीएम सूर्यघर योजना की बैंकवार समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए संबंधित बैंक अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कहा कि शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके लिए आवश्यक है कि बैंकिंग संस्थाएं योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता एवं सक्रियता के साथ कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पात्र हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति में अनावश्यक विलंब न हो तथा स्वरोजगार से जुड़े प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाए। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं एवं छोटे व्यवसायियों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैंक एवं संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

कलेक्टर ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने से पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा। बैठक में स्वयं सहायता समूहों को केसीसी ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से समूहों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने पीएमएफएमई एवं खाद्यान्न उन्नयन योजना के माध्यम से लघु उद्यमों एवं खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने सभी बैंकर्स से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सामाजिक दायित्व के तहत विशेष कार्य करने को कहा। उन्होंने बैंक अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों के लिए कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन एवं बैंकिंग संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी विभाग समन्वय एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए जिले के विकास एवं आम नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आगामी मानसून 2026 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संभावित प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने एवं राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि सभी विभाग पूर्व में तैयार बाढ़ राहत कार्ययोजना का पुनः अवलोकन कर आवश्यक तथ्यों को तत्काल अद्यतन करें तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण कर लें।

निर्देशानुसार जिले में स्थापित सभी वर्षामापक यंत्रों का उचित संधारण एवं नियमित जानकारी प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाएगा। जिन तहसीलों में वर्षामापी यंत्र स्थापित नहीं हैं, वहां तत्काल स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष जिला कार्यालय कंट्रोल रूम में स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07741-232038 निर्धारित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित रहेगा। आपातकालीन स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, फायर ब्रिगेड, पुलिस कंट्रोल रूम तथा जिला चिकित्सालय के दूरभाष नंबरों पर भी तत्काल सूचना दी जा सकेगी। सभी नगरीय निकायों एवं संबंधित कार्यालयों को अपने स्तर पर भी बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि बाढ़ नियंत्रण कक्षों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाई जाए। संभावित पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न, नमक, केरोसिन, जीवनरक्षक दवाइयां सहित आवश्यक सामग्री का पर्याप्त भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए डॉक्टरों की रिस्क्यू टीम गठित करने तथा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में सर्पदंश एवं अन्य जीव-जंतुओं के काटने से संबंधित आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा गया है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जनपद पंचायतों को पेयजल स्रोतों जैसे कुएं एवं हैंडपंपों में ब्लीचिंग पाउडर आदि की व्यवस्था कर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा गया है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ की संभावना बनी रहती है, विशेषकर सकरी एवं हाफ नदी के तटीय गांवों में सतत निगरानी रखी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने एवं अस्थायी राहत शिविरों की व्यवस्था के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों को चिन्हित करने कहा गया है। जिला सेनानी, नगर सेना को बाढ़ बचाव से संबंधित सभी उपकरणों जैसे मोटर बोट, लाइफ जैकेट, रस्सी, सर्च लाइट, मेगाफोन, तारपोलीन एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की मरम्मत कर उपयोग हेतु तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्रों में नालों एवं नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में पोर्टेबल डायविंग पंप की व्यवस्था करने कहा गया है।

बेमेतरा बना दलहन-तिलहन क्षेत्र विस्तार का मॉडल जिला

ग्रीष्मकालीन धान का रकबा घटा, वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ रहे हैं जिले के किसान

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

कृषि प्रधान जिला बेमेतरा ने दलहन एवं तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य में एक प्रेरक मॉडल के रूप में पहचान बनाई है। जिला प्रशासन, कृषि विभाग और किसानों के सामूहिक प्रयासों से ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली वैकल्पिक फसलों की ओर किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है। इससे न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा मिला है, बल्कि किसानों की आय, मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

बेमेतरा जिले की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पर निर्भर है। जिले में खरीफ सीजन के कुल 2.25 लाख हेक्टेयर रकबे में से लगभग 2.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। जिला वृष्टिछाया क्षेत्र अंतर्गत आता है तथा यहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 995 मि.मी. दर्ज की जाती है। जिले में रबी फसलों का कुल रकबा लगभग 1.73 लाख हेक्टेयर है। गत वर्ष 2024-25 में लगभग 26 हजार 680 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की खेती की गई थी, जबकि उस वर्ष जिले में केवल 600 मि.मी. वर्षा हुई थी।

ग्रीष्मकालीन धान से बढ़ा रहा था जल संकट

धान की खेती में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। औसतन 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए 2500 से 3000 लीटर तक पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि ग्रीष्मकालीन धान के लिए लगभग 100 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति मुख्यतः भूमिगत जल स्रोतों से होती है। वृहद स्तर पर ग्रीष्मकालीन धान की खेती के कारण जिले के कई गांवों में जल संकट की स्थिति निर्मित हुई। अनेक हैंडपंप एवं ट्यूबवेल सूख गए, जिससे पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई और समूह जल प्रदाय योजनाओं के संचालन में भी कठिनाई आई। अत्यधिक बिजली खपत, पर्यावरणीय असंतुलन और भूमि की उवर्रा शक्ति में कमी जैसी समस्याएं भी सामने आईं।

ग्राम पंचायतों ने लिया बड़ा निर्णय

जिले में उत्पन्न जल संकट एवं ग्रीष्मकालीन धान को हुए नुकसान को देखते हुए सभी 425 ग्राम पंचायतों ने भविष्य में ग्रीष्मकालीन धान नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया। किसानों ने सामूहिक रूप से कम पानी की आवश्यकता वाली

वैकल्पिक फसलों को अपनाने का निर्णय लिया, जिसे जिले में एक अभिनव एवं सराहनीय पहल माना जा रहा है।

प्रशासन और कृषि विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान

जिला प्रशासन द्वारा किसानों से अपील की गई कि वे ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर दलहन एवं तिलहन फसलों को प्राथमिकता दें। कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने, तकनीकी प्रशिक्षण देने, खेत भ्रमण, कृषक संगोष्ठी और जागरूकता शिविर आयोजित करने जैसे प्रयास किए गए। योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई गई। इन सतत प्रयासों का परिणाम यह रहा की किसानों का विश्वास दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रति बढ़ा और उन्होंने बड़े पैमाने पर इन फसलों की खेती को अपनाया।

ग्रीष्मकालीन धान का रकबा घटा, दलहन-तिलहन में ऐतिहासिक वृद्धि

पिछले वर्ष जिले में जहां 26 हजार 680 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की खेती हुई थी, वहीं इस वर्ष यह घटकर लगभग 5 हजार 139 हेक्टेयर रह गई। इसके विपरीत दलहन फसलों का रकबा 70 हजार 800 हेक्टेयर से बढ़कर 83 हजार 330 हेक्टेयर तक पहुंच गया। वहीं तिलहन फसलों का क्षेत्र 820 हेक्टेयर से बढ़कर 2 हजार 582 हेक्टेयर हो गया, जो लगभग तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है।

दलहन एवं तिलहन क्षेत्र विस्तार से किसानों की आय बढ़ने के साथ-साथ फसल विविधता को बढ़ावा मिला है। इससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पोषण सुरक्षा एवं टिकाऊ कृषि व्यवस्था को मजबूती मिली है। प्रशासन का मानना है कि यह मॉडल भविष्य में अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा।

वैकल्पिक फसलों को व मिलेगा बढ़ावा

जिले में वर्तमान वर्ष में लगभग 5 हजार 139 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की खेती की गई है। आगामी वर्ष से इस क्षेत्र में मक्का, गेहूं, चना, सूरजमुखी, सरसों, मसूर सहित अन्य दलहन-तिलहन एवं कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। किसानों को प्रशिक्षण, संगोष्ठियों एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से कम पानी में अधिक लाभ देने वाली फसलों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

दलहन-तिलहन खरीदी से किसानों में बढ़ा उत्साह

जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी लगातार जारी है। अब तक 54 हजार 300 क्विंटल दलहन-तिलहन का उपार्जन किया जा चुका है तथा किसानों को 14 करोड़ 58 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया है।किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। बेहतर खरीदी व्यवस्था एवं समय पर भुगतान से किसानों में दलहन-तिलहन फसलों के प्रति उत्साह बढ़ा है और अगले वर्ष इसके क्षेत्र विस्तार की व्यापक संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे जल संरक्षण, कम लागत एवं अधिक लाभकारी खेती को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को अपनाएं। बेमेतरा जिले की यह पहल टिकाऊ कृषि विकास और आत्मनिर्भर खेती की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।

जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन

450 बालक-बालिकाओं ने विभिन्न खेलों में लिया प्रशिक्षण

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर 24 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक संचालित हुआ, जिसका समापन शासकीय स्वामी करपात्री जी स्कूल, कवर्धा में आयोजित कार्यक्रम के साथ हुआ। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में हॉकी, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, कराते, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल एवं बेसबॉल सहित विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों द्वारा सुबह एवं शाम नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिविर में जिले के लगभग 450 बालक-बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर खेल कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

समापन समारोह में नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री पवन जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में दीपक सिन्हा पार्षद, आरबी देवांगन डिप्टी कलेक्टर एवं सहायक प्रभारी खेल अधिकारी केसलाल साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा विभिन्न खेल संघों के प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया।

अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास एवं टीम भावना का भी विकास करता है। उन्होंने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास करते हुए जिले एवं राज्य का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। शिविर के सफल संचालन में राजा जोशी, प्रमोद कौशिक, मोहम्मद गनी खान, कुमार चन्द्रवंशी, मोहम्मद साजिद खान, युवराज प्रमाण, गुरुकुल पब्लिक स्कूल, आकाश राजपूत कराते संघ, मनीष निषाद सहित सभी प्रशिक्षकों का विशेष सहयोग रहा।

25 मई तक मई-जून माह का शत प्रतिशत खाद्यान्न वितरण पूर्ण करने के निर्देश

कवर्धा। राज्य शासन द्वारा जिलों में खाद्य विभाग को आगामी 25 मई तक मई और जून माह के खाद्यान्न का शत प्रतिशत वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों को 25 मई तक नियमित रूप से संचालित करने कहा गया है, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न प्राप्त हो सके।

हितग्राहियों को समय सीमा की जानकारी देने के लिए ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर आवश्यक मुनादी तथा व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला खाद्य अधिकारी ने कहा है कि सभी पात्र हितग्राही निर्धारित तिथि के भीतर अपना खाद्यान्न प्राप्त कर लें, ताकि कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि जिले की सभी 516 राशन दुकानों में अप्रैल, मई और जून माह के राशन का भंडारण शत प्रतिशत किया जा चुका है।

खुशियों की चाबी : मंत्री बघेल ने हितग्राहियों को सौंपे पक्के मकानों की चाबियां

सुशासन तिहार शिविर में पीएम आवास पाकर ग्रामीणों के चेहरे पर दिखी खुशी, अपने घर का सपना हुआ साकार

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आज जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत कटई में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने क्षेत्र के ग्रामीण हितग्राहियों को उनके नव निर्मित पक्के मकानों की चाबियां सौंपकर गृह प्रवेश की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर लाभार्थियों के चेहरों पर अपने सपनों का आशियाना मिलने की खुशी साफ झलक रही थी।

कार्यक्रम के दौरान खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि कोई भी परिवार कच्चे और असुरक्षित मकानों में रहने को मजबूर न हो।

कच्चे मकानों से मिली मुक्ति, पक्के घरों में शुरू हुई नई जिंदगी

वर्षों से कच्चे मकानों में जीवन यापन

कर रहे ग्रामीण परिवारों के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहा। जैसे ही हितग्राहियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी गईं, पूरे परिसर में खुशी और भावुकता का माहौल बन गया। कई हितग्राहियों ने बताया कि बरसात के दिनों में कच्चे मकानों में रहना बेहद कठिन होता था, लेकिन अब पक्के मकान मिलने से उनका परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेगा।

एक लाभार्थी ने भावुक होकर कहा आज मेरा खुद के पक्के घर का सपना सच हो गया। अब हमारा परिवार सुरक्षित और खुश है। सरकार ने हमें नई जिंदगी दी है।

सुशासन तिहार बना जनकल्याण और विश्वास का माध्यम

सुशासन तिहार शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। शिविर में अधिकारियों द्वारा योजनाओं के त्वरित निराकरण, जनसमस्याओं के समाधान और पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई। मंत्री श्री बघेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए।

"चिरायु" योजना से बेमेतरा के सैकड़ों बच्चों को मिला नया जीवन

स्वास्थ्य विभाग जिला बेमेतरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम "चिरायु" योजना के माध्यम से बेमेतरा जिले में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, बीमारियों की प्रारंभिक पहचान एवं निःशुल्क उपचार कलेक्टर सुश्री प्रतिभा ममगाईं के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ अमृत लाल रोहलेडर के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री लता बंजारे के सक्रियता में सतत रूप से किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बेमेतरा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में "4D" अर्थात जन्मजात दोष, बीमारी, पोषण संबंधी कमियों और विकासात्मक समस्याओं एवं विकलांगता की समय पर पहचान कर समुचित उपचार एवं परामर्श उपलब्ध कराना है। जिले में 9 चिरायु दलों का संचालन सहायक जिला नोडल अधिकारी डॉ ऋषभ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में बेमेतरा जिले में कुल 9 चिरायु दल प्रत्येक विकासखण्ड में दो एवं शहरी क्षेत्र में एक सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक दल में 1 पुरुष चिकित्सक, 1 महिला चिकित्सक, 1 फार्मासिस्ट तथा 1 ए.एन.एम. सम्मिलित है। इन प्रशिक्षित मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा प्रतिवर्ष जिले के 1300 शासकीय विद्यालयों के 1लाख 45 हजार विद्यार्थियों एवं 1200 आंगनबाड़ी केंद्रों के 61 हजार 311 बच्चों में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कर बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है।

सबका सपना - घर हो अपना का सपना हो रहा साकार

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में हजारों परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना से गरीब परिवारों को न केवल सुरक्षित आवास मिल रहा है, बल्कि उनके जीवन स्तर, सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास में भी सकारात्मक बदलाव आ रहा है। ग्राम पंचायत कटई में आयोजित यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास और जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

सुशासन तिहार : मुख्यमंत्री साय का सख्त रुख, कोरिया के सहायक आयुक्त निलंबित

सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी में पेयजल संकट व खराब परीक्षा परिणाम पर जताई नाराजगी, कलेक्टरों को दिए कड़े निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-चिरमिरी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को सुशासन तिहार के तहत सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी जिले का औचक दौरा किया। इस दौरान शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी और ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं।

चिरमिरी में तीनों जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने पेयजल समस्या और स्कूली परीक्षा परिणामों पर गहरी नाराजगी जताई। कोरिया में खाद वितरण में गड़बड़ी के मामले में सहायक आयुक्त एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए।

पेयजल आपूर्ति में कोताही पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकटग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की नियमित आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। जिन इलाकों में कमी है, वहां टैंकर से पानी पहुंचाना कलेक्टरों की सीधी जिम्मेदारी होगी। कोताही पर कलेक्टर जवाबदेह माने जाएंगे।

परीक्षा परिणाम पर नाराजगी, पढ़ाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश

तीनों जिलों के खराब शालेय परीक्षा परिणाम पर नाराजगी जताते हुए सीएम ने कलेक्टरों को आगामी सत्र के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाने को कहा। स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए, ताकि परिणाम में सुधार हो सके।

मौसमी बीमारियों और पीएम आवास पर भी निर्देश

मुख्यमंत्री ने बरसात से पहले सभी पेयजल स्रोतों की सफाई और क्लोरिनेशन अनिवार्य रूप से कराने को कहा। पीएम आवास योजना के निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। गड़बड़ी या हितग्राही की परेशानी पर कलेक्टरों को सीधा जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

समीक्षा बैठक चिरमिरी स्थित एसईसीएल के तानसेन भवन से वर्चुअल हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक भईया लाल राजवाड़े, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, आयुक्त जनसंपर्क रजत बंसल सहित तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। सूरजपुर के ग्राम रामपुर में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से आत्मीयता से मुलाकात की। तेंदूपत्ता संग्राहक महिलाओं को चरण पादुका पहनाई और बच्चों का अन्नप्राशन-नामकरण भी किया।

दिग्विजय स्टेडियम समिति के नए पदाधिकारियों ने संभाला पदभार, डॉ. रमन सिंह बोले : राजनांदगांव बनेगा शतरंज का हब

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

स्टेडियम के विकास के लिए 29 लाख मंजूर, एथलेटिक ट्रैक और बैडमिंटन कोर्ट को भी मिली मंजूरी

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह बुधवार को दिग्विजय स्टेडियम समिति के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समिति के नवनियुक्त सचिव रमेश पटेल और सहसचिव योगेश बागड़ी को बधाई दी।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि दिग्विजय स्टेडियम में बास्केटबाल, क्रिकेट, टेनिस, स्नूकर, बिलियर्ड्स और शतरंज जैसे खेलों का अच्छा उपयोग हो रहा है। राजनांदगांव जिले को शतरंज के हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने स्टेडियम को सक्रिय कर खेल गतिविधियां बढ़ाने को कहा।

उन्होंने बताया कि स्टेडियम के समतलीकरण और निर्माण के लिए 15 लाख रुपए तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिए 14 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। कुल 29 लाख रुपए के कार्य एक सप्ताह में स्वीकृत हो जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अब तक ढाई हजार करोड़ रुपए जिले के विकास के लिए स्वीकृत किए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन में राजनांदगांव को शामिल करने से जिले के विकास की रूपरेखा तैयार होगी।

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का टेंडर लग गया है। नवागांव में 8 करोड़ की लागत से एथलेटिक ट्रैक बनेगा। बैडमिंटन कोर्ट का भी अनुमोदन हो गया है। स्टेडियम के मेंटेनेंस के लिए दुकानें किराए पर देकर फंड जनरेट किया जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की।

महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि नए पदाधिकारियों से खेल प्रेमियों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा, श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष योगेश्वर दत्त मिश्रा, सहकारी बैंक अध्यक्ष सचिन बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव, राजगामी संपदा अध्यक्ष पूर्णिमा साहू, मनोज निर्वाणी, खूबचंद पारख, संतोष अग्रवाल, कोमल राजपूत सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

बघेरा-झुराडबरी में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई, पटवारी को नोटिस

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

2-3 साल से चल रहा था बिना अनुमति निर्माण, तहसीलदार ने टीम के साथ हटाए अवैध ढांचे

ग्राम बघेरा और झुराडबरी में अवैध प्लाटिंग और बिना अनुमति निर्माण कार्य करने के मामले में तहसीलदार राजनांदगांव प्यारेलाल नाग ने पटवारी हल्का नंबर 18 धनसिंग कोमरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

कई खसरों पर मिला अवैध निर्माण

तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम ने बघेरा और झुराडबरी क्षेत्र के खसरा नंबर 492/2, 493/2, 494, 415, 505/2, 500/1, 510/1, 510/4, 511/1, 512/1, 505/3, 510/3, 503/1, 510/2, 511/3, 502/1, 504/3, 513/1, 513/2, 513/3, 500, 415/1, 410/2, 410/5, 344/1, 316/1, 334/1, 334/2, 334/3, 335/1, 335/2, 336, 337, 339/1, 340, 342, 343/1, 343/2, 345/1 और 345/2 की भूमि का निरीक्षण किया। जांच में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अवैध प्लाटिंग, बाउंड्रीवाल, गेट, तार फेंसिंग और मकान निर्माण पाया गया। राजस्व अमले ने मौके पर अवैध संरचनाओं को हटाया।

2 दिन में मांगा जवाब

जांच में सामने आया कि यह निर्माण कार्य पिछले 2 से 3 साल से चल रहा था। पटवारी ने इसकी सूचना पहले नहीं दी थी। इसे पदीय दायित्वों के विरुद्ध मानते हुए पटवारी धनसिंग कोमरे को 2 दिन के भीतर स्वयं उपस्थित होकर या लिखित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

चोरी व सट्टा गिरोह का खुलासा करने वाली दुर्ग पुलिस टीम सम्मानित

आईजी अभिषेक शांडिल्य ने 33 हजार से अधिक का नगद पुरस्कार दिया, 13 आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-भिलाई

पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज अभिषेक शांडिल्य ने चोरी और ऑनलाइन म्यूल अकाउंट/सट्टा प्रकरणों में सराहनीय कार्य करने वाली दुर्ग पुलिस टीम को 33 हजार रुपए से अधिक के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया।

दो टीमों को मिला इनाम

चोरी के मामलों में लगन से काम करने वाली टीम को 23,500 रुपए और ऑनलाइन सट्टा प्रकरण में सटीक कार्रवाई करने वाली टीम को 9,750 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। आईजी ने बुधवार को कार्यालय में टीम के सदस्यों से मिलकर उन्हें सम्मानित किया।

13 आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख फ्रीज

16 मई को एसीसीयू टीम ने ऑनलाइन सट्टा और म्यूल अकाउंट मामले में 13 आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने लोगों के बैंक खाते खुलवाकर पासबुक, एटीएम, सिम और चेकबुक लेकर सट्टे में रकम का लेनदेन करना कबूला। कार्रवाई में नगद राशि, 46 मोबाइल, 9 लैपटॉप, कई सिम कार्ड और बैंक खातों में जमा करीब 10 लाख रुपए की जानकारी मिली।

मेरठ गिरोह से 400 ग्राम सोना बरामद

थाना सुपेला और पद्मनाभपुर की टीम ने एसीसीयू के सहयोग से तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर मेरठ के चोर गिरोह का पता लगाया। टीम ने मेरठ जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर और जबलपुर में चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया। इनसे करीब 400 ग्राम सोना, लाखों का चोरी का माल और नगद राशि बरामद हुई।

आईजी अभिषेक शांडिल्य ने इसे पुलिस टीम की मेहनत और उत्कृष्ट विवेचना का परिणाम बताया। उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित किया।

फर्जी निवेश कंपनी बनाकर 13.60 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

फॉरेक्स ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का झांसा देकर की धोखाधड़ी, पुलिस को अन्य आरोपियों की तलाश

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने फर्जी निवेश योजना के नाम पर 13 लाख 60 हजार रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादा लाभ का झांसा देकर युवक से अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा कराई थी।

कैसे हुई ठगी : गंजपारा दुर्ग निवासी 27 वर्षीय दीपक जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2024 में आरोपियों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग और निवेश कंपनी में अधिक लाभांश का झांसा दिया। आरोपियों ने कहा कि निवेश की राशि पर हर महीने लाभ मिलेगा और मूलधन सुरक्षित रहेगा। इसके बाद प्रार्थी से आरटीजीएस और ऑनलाइन माध्यम से 13,60,000 रुपए जमा कराए गए। कुछ समय बाद कंपनी बंद हो गई। प्रार्थी को न लाभांश मिला और न जमा राशि वापस हुई।

आरोपी पुलिस रिमांड पर : शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 224/2026 धारा 420, 34 भादवि के तहत केस दर्ज किया। विवेचना में आरोपी राजेन्द्र कुमार ताम्रकार, उम्र 50 वर्ष, निवासी तामेश्वरा वार्ड-30, हाल जवाहर नगर वार्ड-18 दुर्ग को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने साथियों के साथ फर्जी योजना चलाकर ठगी करना कबूला। आरोपी को न्यायालय से पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

जप्त सामान और जांच जारी : पुलिस ने आरोपी से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, बैंक दस्तावेज और लेन-देन संबंधी कागजात जब्त किए हैं। मामले में अन्य फरार आरोपियों और बैंक खातों की जांच जारी है।

नौकरी दिलाने के नाम पर 7.50 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। भिलाई नगर पुलिस ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 7 लाख 50 हजार रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रार्थी के बेटे को नौकरी लगाने का भरोसा देकर 2022 से 2024 के बीच रकम ली थी।

6 महीने में नियुक्ति पत्र का दिया था भरोसा : तालपुरी निवासी राजेन्द्र कुमार बंछोर ने 21 मई को थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्रार्थी ने बताया कि परिचित अमनदीप सोढी ने उसके बेटे को नौकरी दिलाने का झांसा दिया। आरोपी ने 10 जुलाई 2022 से 2024 के बीच कुल 7,50,000 रुपए नगद लिए और छह महीने में नियुक्ति पत्र दिलाने का आश्वासन दिया। लंबा समय बीतने पर भी न नौकरी मिली और न रकम वापस हुई।

न्यायिक रिमांड पर भेजा : शिकायत पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 267/2026 धारा 420 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया। जांच में आरोपी अमनदीप सोढी, उम्र 36 वर्ष, निवासी बी-1, छ.ग.कॉलेज धनोरा के पास, जिला दुर्ग को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने दस्तावेजी साक्ष्य और लेन-देन संबंधी कागजात जब्त किए हैं।

धनोरा श्मशान घाट के पास सट्टा लिखते 3 गिरफ्तार, नगदी व मोबाइल जब्त

भिलाई। पदमनाभपुर पुलिस ने ग्राम धनोरा स्थित श्मशान घाट के पास छापा मारकर सट्टा-पट्टी लिख रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 10 सट्टा पर्ची, 3 मोबाइल, डॉट पेन और 2020 रुपए नगद जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सलमान रजा (27) निवासी रूआबांधा आजाद चौक, असलम खान (25) निवासी रूआबांधा मस्जिद के पास और आयुष शाह (20) निवासी रूआबांधा यादव चौक, थाना भिलाई नगर के रूप में हुई है। तीनों के खिलाफ थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 291/2026 धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100